दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

आज का विचार

आपको जीवन का प्रथम एवं अंतिम चरण खुद के साथ आत्म-साक्षात्कार करना होना चाहिए। अगर आप खुद को जान सके तो आपका जीवन सफल हो सकता है।

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । वीरवार, 3 अप्रैल, 2025 वर्ष 23, अंक 82, मूल्य: 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

जब तक पंजाब से नशे का नामो-निशान नहीं मिटता, तब तक चैन से न बैठें - केजरीवाल की युवाओं से अपील

पिछली सरकारों ने गैर-कानूनी तरीके से पैसा कमाने के लिए नशों के व्यापारियों को संरक्षण दिया

संवाददाता
लुधियाना

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से नशे का नामो-निशान मिटाने के लिए प्रांत के युवाओं से नशों के खिलाफ निर्णायक जंग में सहयोग करने का आह्वान किया।

आज यहां नशे के खिलाफ मार्च को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रांत से नशे को पूरी तरह से समाप्त करने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि अगर इस बुराई का खात्मा नहीं किया गया तो यह एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी जिससे प्रांत और उसकी आने वाली पीढ़ियों को बहुत नुकसान होगा। अरविंद केजरीवाल ने युवाओं से नशों से दूर रहने की अपील की क्योंकि यह बुराई उनके और उनके परिवार के जीवन को तबाह कर देगी। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि पंजाब में पिछली सरकारों ने प्रांत में नशों के व्यापारियों को संरक्षण दिया था और उनके बड़े नेता भी इसमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि गैर-कानूनी तरीके से पैसा कमाने के लिए इन लालची नेताओं ने प्रांत में नशों के व्यापार को प्रोत्साहित किया जिससे हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा, ह्लईश्वर और राज्य के लोग इन राजनीतिक नेताओं को इस बड़े पाप के लिए कभी माफ नहीं करेंगे और उन्हें इस अपराध की सजा जरूर मिलेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रांत सरकार ने पिछले 30 दिनों में नशों के खिलाफ उदाहरणीय काम किया है और नशा तस्करों द्वारा बनाए गए बड़े-बड़े महल भी ढहाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके जेल भेजा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां नशा तस्करों को पकड़कर नशे की सप्लाई लाइन तोड़ रही हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके प्रशंसनीय भूमिका निभा रही हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने आगे कहा कि इस घृणित अपराध में शामिल लोगों के लिए मिसाली सजा सुनिश्चित करने के लिए नशा तस्करों की संपत्ति जब्त/ढहाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने नशों के प्रति कोई समझौता न करने की नीति अपनाई हुई है और इस समस्या के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया गया है। युवाओं के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, ह्लअगर आपका कोई दोस्त या परिवार का सदस्य नशे की चपेट में है तो इसे समय पर रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित करना चाहिए।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में नशों के प्रसार को रोकना और हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचाना बहुत जरूरी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने गांव और क्षेत्र की जिम्मेदारी लें और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9779100200 पर संपर्क करके नशे की समस्या को रोकने और अपने क्षेत्र में नशा तस्करों की किसी भी गतिविधि की जानकारी दें। अरविंद केजरीवाल ने युवाओं से कहा कि वे प्रण लें कि वे नशा नहीं करेंगे, वे किसी को भी नशा बेचने की इजाजत नहीं देंगे और नशों के खिलाफ अभियान का समर्थन करेंगे।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा पीड़ितों के उपचार के लिए सरकार ओ.पी.डी. स्तर पर नशा मुक्ति सेवाओं के लिए ह्यओट क्लीनिकह्व चला रही है। उन्होंने कहा कि नशा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए राज्य में पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि युवाओं को नशों से दूर रखने के लिए प्रांत के हर गांव में खेल के मैदान और जिम खोले जा रहे हैं।

कांग्रेस ने किया था वक्फ को संविधान से ऊपर शक्ति देने का पाप: अमित शाह

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वक्फ विधेयक में 2013 में संशोधन कर वक्फ को संविधान से भी ऊपर असीमित शक्ति देने का पाप किया था। इसके कारण 2013 से 2025 तक वक्फ की संपत्ति में बड़ा इजाफा हुआ है। साथ ही उस समय हड़पी गई जमीन के खिलाफ पीड़ित का न्यायालय के पास जाने का अधिकार भी छीन लिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़े गिनाते हुए बताया कि 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन के बाद से 2025 के बीच में वक्फ संपत्ति में 21 लाख एकड़ जमीन की वृद्धि हुई है जबकि यह 2013 तक केवल 18 लाख एकड़ थी।

फोटो : हि.स.

उन्होंने कहा, सरकार या संगठन का कोई निर्णय अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति की जमीन ली गई है, वह कहां जाएगा? कांग्रेस ने वोट-बैंक की राजनीति के लिए ऐसा किया और हम इसे अस्वीकार कर रहे हैं। शिकायतों वाला कोई भी व्यक्ति अदालत से संपर्क कर सकता है। शाह ने कहा कि विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के बाद लाया गया है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्ति का बेहतर प्रबंधन है ताकि इससे होने वाली आमदनी को बढ़ाया जा सके। आमदनी का इस्तेमाल मुसलमानों के विकास के लिए होगा लेकिन वर्तमान में पैसा चोरी हो रहा है। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद इस चोरी को रोकेंगे।

इस संबंध में उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 2001-12 के बीच दो लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति निजी संस्थानों को सौ साल की लीज पर हस्तांतरित कर दी गई। बेंगलुरु में उच्च न्यायालय को बीच में दखल देना पड़ा और 602 एकड़ भूमि को जब्त करने से रोकना पड़ा। ये पैसा देश के गरीब मुसलमानों का है, ये धन्नासेठों की चोरी के लिए नहीं है। गृह मंत्री ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बयान का उल्लेख किया और कहा कि तब उन्होंने कहा था कि वह वक्फ पर एक सख्त कानून चाहते थे और उन लोगों को जेल में डालना चाहते थे, जो चोरी कर रहे थे। नरेन्द्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव की इच्छाओं को पूरा किया है। विपक्ष पर भ्रम फैलाने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी पिछड़े वर्गों या मुसलमानों के बारे में चिंतित नहीं हैं। वर्षों से उन्होंने जातिवाद और तुष्टीकरण के आधार पर काम किया। इन समुदायों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक सोची समझी रणनीति के माध्यम से परिवार-केंद्रित राजनीति को बढ़ावा दिया। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने जातिवाद, तुष्टीकरण और भाई -भतीजावाद को मिटा दिया है और बजाय विकास की राजनीति की स्थापना की है।

शाह ने इस दौरान स्पष्ट किया कि संसद सर्वोपरि है और उसमें पारित कानून को सभी को मानना होगा। एक सदस्य ने कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय इस कानून को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, ह्लकोई भी कैसे कह सकता है, 'हम इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे'? यह भारत सरकार का एक कानून है, और यह सभी पर लागू होता है। यह सभी के लिए बाध्यकारी है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ की अवधारणा इसके उपयोग पर आधारित होनी चाहिए और उपयोग की जा रही भूमि का अभी तक पंजीकरण हो जाना चाहिए था । लेकिन मुगल काल की प्रथाओं के आधार पर आज किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता।

गैर मुस्लिम को शामिल किए जाने पर शाह ने वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दोनों कानून के तहत किसी द्वारा वक्फ को दान की गई संपत्ति की प्रशासन देखभाल करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सही मकसद के लिए उसका इस्तेमाल हो। इसके अलावा मुस्लिमों की धार्मिक गतिविधियों के लिए दान के माध्यम से गठित ट्रस्ट में सरकार का हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं है। मुतावल्ली और वकीफ मुस्लिम समुदाय से होगा।

अमित शाह ने कहा कि विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के बाद लाया गया है। 2013 में हुए संशोधन में दोनों सदनों में 5.4 से 5.5 घंटे चर्चा की गई थी। इसके विपरीत हम विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर कुल 16 घंटे चर्चा करायेंगे।

अमित शाह का अखिलेश पर तंज, कहा- आप 25 साल तक सपा अध्यक्ष बने रहेंगे

नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विषय से हटकर भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में देरी को लेकर कटाक्ष किया। इस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमति शाह ने उसी अंदाज में वंशवाद को लेकर सपा पर तंज कसा। लोकसभा में चर्चा के दौरान अखिलेश ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा कि भाजपा में आंतरिक संघर्ष चल रहा है। एक पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा किया जाता है, वह अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। गृहमंत्री शाह ने उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश जी ने हंसते-हंसते कहा है, इसलिए मैं भी उसी अंदाज में जवाब दूंगा। शाह ने कहा, ह्मेरे सामने जितनी भी पार्टियां हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कुछ परिवार के लोग ही करेंगे। हमें 12-13 करोड़ सदस्यों में से प्रक्रिया के बाद चुनना होता है। इसलिए इसमें समय लगता है। आपके मामले में इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूं कि आप 25 साल तक अध्यक्ष बने रहेंगे।

दो चरणों में पूरा हुआ भारतीय और रूसी नौसेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास 'इंद्र'

जटिल सामरिक युद्धाभ्यास, हवाई तथा सतही लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया

फोटो : हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

भारतीय और रूसी नौसेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास 'इंद्र' बुधवार को खत्म हो गया। दो चरणों में हुआ यह अभ्यास समुद्री सहयोग का प्रतीक बन गया है, जो दोनों देशों की नौसेना की अंतर-संचालन क्षमता और परिचालन तालमेल को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में दोनों नौसेनाएं जटिल सामरिक युद्धाभ्यास, हवाई तथा सतही लक्ष्यों पर संयुक्त अभ्यास में शामिल हुईं।

वर्ष 2003 में शुरू हुआ भारत और रूस के बीच स्थायी समुद्री साझेदारी का प्रतीक यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों का प्रतीक है। भारत-रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च से चेन्नई के तट पर शुरू हुआ था। दोनों देशों के जहाजों ने बंदरगाह चरण की शुरूआत की और 30 मार्च तक अभ्यास किया। बंदरगाह चरण में विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान, पारस्परिक दौरे, खेल कार्यक्रम और दोनों नौसेनाओं के कर्मियों के बीच प्री-सेल ब्रीफिंग हुई।

इसके बाद बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण 31 मार्च से 02 अप्रैल तक चला। समुद्री चरण में उन्नत नौसैनिक अभ्यास हुए, जिसमें सामरिक युद्धाभ्यास, लाइव हथियार फायरिंग, एंटी-एयर ऑपरेशन, अंडरवे रिप्लेनिशमेंट, हेलीकॉप्टर क्रॉस-डेक लैंडिंग और सी-राइडर्स का आदान-प्रदान शामिल रहा। इस अभ्यास में रूसी नौसेना के जहाज पेचंगा, रेज्की और अलदार त्सिडेंझापोव के साथ-साथ भारतीय नौसेना के जहाज राणा, कुथार और समुद्री गश्ती विमान पी8आई ने हिस्सा लिया।

दो चरणों में हुआ यह अभ्यास समुद्री सहयोग का प्रतीक बन गया है, जो दोनों देशों की नौसेना की अंतर-संचालन क्षमता और परिचालन तालमेल को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। इन अभ्यासों और बातचीत का उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ाना, मैत्री संबंधों को मजबूत करना, सर्वोत्तम परिचालन प्रथाओं का आदान-प्रदान करना तथा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करना था।

प्रधानमंत्री ने एनईपी 2020 को भारत के बौद्धिक पुनर्जागरण के रूप में सराहा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के शिक्षा क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सराहना करते हुए इसे भारत का बौद्धिक पुनर्जागरण बताया। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा और नवाचार के माध्यम से एक आत्मनिर्भर, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री ने बुधवार को एक्स पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पिछले दशक में भारत के शिक्षा क्षेत्र में किस तरह ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। एनईपी 2020 एक सुधार से कहीं अधिक है; यह भारत का बौद्धिक पुनर्जागरण है, जो शिक्षा और नवाचार के माध्यम से एक आत्मनिर्भर, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करता है।

मोदी ने कहा-नवरात्रि में मां अम्बे की उपासना कर देती है भावविभोर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नवरात्रि के चौथे दिन मां अम्बे की पूजा के महत्व पर चर्चा की है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरूआत 30 मार्च से हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, '' नवरात्रि में मां अम्बे की उपासना सभी भक्तों को भावविभोर कर देती है। देवी मां के स्वरूपों को समर्पित यह स्तुति अलौकिक अनुभूति देने वाली है। आप भी सुनिएह्व।'' मां अम्बे को दुर्गा, शक्ति, भगवती, चंडी आदि नामों से भी जाना जाता है। उनके कुछ प्रमुख नाम हैं- सती, नवदुर्गा, आदि शक्ति, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इस बार चैत्र नवरात्रि की खास बात यह है कि वह नौ दिन की नहीं बल्कि आठ दिन की होगी। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से हिन्दू नववर्ष की भी शुरूआत होती है। इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना (कलश स्थापना) की जाती है।

पाकिस्तानी सेना ने पुंछ की नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का किया उल्लंघन

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करते हुए जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर गोलीबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने नियंत्रित और संतुलित जवाबी कार्रवाई की। जम्मू स्थित रक्षा पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने बुधवार को एक बयान में बताया कि पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का यह उल्लंघन मंगलवार को दोपहर 1.10 बजे हुआ। हालांकि, उन्होंने भारत की जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान की ओर से किसी के हताहत होने का कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि

फोटो : हि.स.

विस्फोट और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में दुश्मन के पांच सैनिक घायल हो गए।

दरअसल, 01 अप्रैल को नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ के कारण कृष्णा घाटी सेक्टर में एक माइन ब्लास्ट हुआ। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने बिना उकसावे के गोलीबारी और संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने नियंत्रित और संतुलित तरीके से प्रभावी ढंग से जवाब दिया। स्थिति नियंत्रण में है और इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के लिए महानिदेशक सैन्य अभियान (डीजीएमओ) के बीच 2021 की सहमति के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व को दोहराती है।

मुस्लिम संगठनों ने वक्फ विधेयक के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए कमर कसी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

लोकसभा में सरकार के जरिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करने के बाद से ही मुस्लिम संगठनों की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद में विधेयक पेश करने से पहले प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करके अपने रुख को पूरी तरह से साफ कर दिया है।

बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि बोर्ड मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर एक देशव्यापी आंदोलन चलाएगा। इसके अलावा अदालती प्रक्रिया का भी सहारा लेने की बात उन्होंने कही है। उनका कहना है कि अब यह लड़ाई अंतिम समय तक लड़ी जाएगी जब तक की वक्फ संशोधन विधेयक वापस नहीं लिया जाएगा। जमीअत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भी संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहां है कि केंद्र सरकार की मंशा और इस बिल को पेश करने की प्रक्रिया सही नहीं है। जबरन इस बिल को पेश करके संख्या बल पर पास कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं और इस बिल के खिलाफ एक लंबे आंदोलन चलाने की तैयारी के लिए मुसलमान से कमर कसने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल के समर्थन में जो लोग हैं वह सरकार के साथ है और हम उन्हें अच्छी तरह से पहचान रहे हैं।

फोटो : हि.स.

जमाअत ए इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सआदतउल्लाह हुसैनी ने भी एक बयान में इस बिल को संसद में पेश करने और सरकार के जरिए पास करने की कोशिश की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह बिल मुसलमान को किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। लेकिन सरकार अपने अड़ियल रुख को अपनाते हुए इसे पास करना चाहती है। उनका कहना है कि हम इस बिल के खिलाफ हैं और इसके लिए लंबे आंदोलन के लिए भी तैयार हैं।

ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने भी संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक को किसी भी तरह से मुसलमान के लिए उचित नहीं होने की बात की है।

काउंसिल सह महासचिव शेख निजामुद्दीनने कहा है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों को हड़पने और वक्फ काउंसिल, वक्फ बोर्ड को कमजोर करने की एक साजिश है। यह हमें कबूल नही है। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ इसके खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए तैयार है।

राजद प्रमुख लालू यादव की तबियत बिगड़ी डॉक्टरों ने दिल्ली जाने की दी सलाह

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। ब्लड शुगर बढ़ने के कारण उनकी स्थिति खराब हो गई, जिसके चलते डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली जाने की सलाह दी है। लालू यादव बीते दो दिनों से ब्लड शुगर बढ़ने की समस्या से जूझ रहे थे। बुधवार सुबह उनकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों की एक टीम पटना स्थित राबड़ी आवास पर उनकी निगरानी में लगी हुई है। चिकित्सकों के मुताबिक, उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है और जल्द ही उन्हें दिल्ली भेजा जा सकता है। पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। बहुत जल्द ही लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से दिल्ली ले जाया जा सकता है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम लालू यादव की हालत स्थिर बता रही है। राजनीतिक रूप से देखें तो, हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। तेजस्वी के लिए माहौल बनाने के लिए वह जिलों का दौरा भी कर रहे थे। यही नहीं पटना में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरना स्थल पर भी नजर आए थे। उन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ बैठकर उनका हौसला भी बुलंद किया था। ऐसे में अचानक आज लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने की खबर आई है, जो उनके समर्थकों के लिए चिंता का विषय है। उल्लेखनीय है कि लालू यादव डायबिटीज के मरीज हैं। उनकी किडनी ट्रांसप्लांट भी हुई है। बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें अपनी एक किडनी दी है। सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी।

पांच करोड़ से बनेगा चामशु पुल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किया शिलान्यास

सड़क सुविधा का विस्तार, ग्रामीणों को राहत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार की प्राथमिकता

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र जुब्बल-नावर-कोटखाई में करोड़ों की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले चामशु पुल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह पुल जुब्बल और रोहडू क्षेत्र को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे रावीं, भोलाड़ और मांदल पंचायतों के निवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और पब्बर नदी के समीप स्थित किसानों को भी लाभ होगा। इसके अलावा, सरस्वती नगर में बने पुल पर वाहनों की आवाजाही में भी कमी आएगी।

फोटो : हि.स.

शिक्षा मंत्री ने 67 लाख रुपये की लागत से निर्मित अंटी सभाड़-धारकोटी सेरटी सड़क का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी और वे अपनी फसलें आसानी से बाजार तक पहुंचा सकेंगे। कुड्डू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में क्षेत्र में कई विकास कार्य किए गए हैं। कुड्डू, खनाशनी और आसपास के क्षेत्रों में 15 सड़कों का निर्माण हुआ है, जबकि पंद्राणु और सोलंग क्षेत्र में 6 नई सड़कों को स्वीकृति दी गई है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पंद्राणु का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि नंदपुर, दखरेंटू और राथल स्कूलों के नए भवनों का निर्माण भी जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझने और उन्हें प्राथमिकता से हल करने का प्रयास कर रही है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर गंभीर है और इस दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। बीते दो वर्षों में शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक के 4 पद, उप निदेशक के 37 पद, कॉलेज प्रिंसिपल के 119 पद, स्कूल प्रिंसिपल के 313 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 483 पद और पीजीटी के 700 पदों को भरा गया है। इसके अलावा हजारों अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सरकार ने प्री-नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के लिए अलग निदेशालय तथा कॉलेज शिक्षा के लिए अलग निदेशालय की स्थापना की है।

वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों को कमजोर करने के लिए बनाया गया है: मुफ्ती

श्रीनगर। पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने आज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मुझे भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है लेकिन धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, उन्हें आगे आना चाहिए क्योंकि इस देश को संविधान के अनुसार चलना है। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों को उत्पीड़न, लक्षित लिंचिंग की घटनाओं और कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण का सामना करना पड़ा है और उन्होंने हिंदुओं से ऐसे अन्याय के खिलाफ उठने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुसलमानों को कमजोर करने की साजिश है और पिछले 10-11 वर्षों में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है और लिंचिंग की घटनाएं और कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण आम बात हो गई है। पीडीपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि देश गांधी का है और इसे संविधान के अनुसार चलाया जाना चाहिए, न कि भाजपा के एजेंडे के अनुसार। मुफ्ती ने हिंदुओं से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया ताकि भारत म्यांमार जैसा न बन जाए या मुसलमानों को कश्मीरी पंडितों जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े, जिसके लिए हमें शर्म आती है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस देश को तोड़ रही है और भारत के लोगों से एकजुट होने और विभाजनकारी रणनीति का विरोध करने का आह्वान किया।

शिमला में नेपाली युवक को उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

जिला शिमला के ठियोग थाना क्षेत्र में एक नेपाली युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सुशील (30 से 40 वर्ष) के रूप में हुई है। हत्या का आरोप नेपाली मूल के ही एक अन्य व्यक्ति पर है जो घटना के बाद से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या शराब के नशे में की गई। मृतक और आरोपी दोनों ठियोग के एक सेब बगीचे में मजदूरी करते थे। स्थानीय निवासी व बागवान संजीव कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

शिकायतकर्ता संजीव कुमार के मुताबिक उन्होंने करीब 15 दिन पहले नेपाली मूल के पारस राम को अपने बगीचे में काम पर रखा था। पारस राम उनके घर के पास ही एक तंबू में रहता था। 31 मार्च की सुबह 10 बजे वह ठियोग बाजार जाने की बात कहकर निकला था। अगले दिन 1 अप्रैल की सुबह करीब 9 बजे जब संजीव कुमार बगीचे की ओर जा रहे थे तो उन्होंने पारस राम के तंबू के पास एक व्यक्ति को खून से लथपथ पड़ा देखा। पास जाकर देखने पर उन्होंने पाया कि मृतक सुशील था जो पास के इलाके में रहता था। जब उन्होंने पारस राम को आवाज दी तो वह मौके पर नहीं मिला।

संजीव कुमार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और आशंका जताई कि पारस राम ने शराब के नशे में सुशील की हत्या कर दी और फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ठियोग पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपी की तलाश में आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि यह गंभीर मामला है और पुलिस सभी संभावित कोणों से जांच कर रही है। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के पीछे के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

वक्फ संशोधन विधेयक से वक्फ संपत्तियों को मिलेगा संरक्षण: डॉ. राजीव बिंदल

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक वास्तव में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि 2006 में गठित एक कमीशन और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों पर गैरकानूनी कब्जों की बात सामने आई थी, जिससे इनकी आमदनी लगातार घट रही थी। 2008 में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट ने भी इस समस्या को उजागर किया था। डॉ. बिंदल ने बुधवार को एक बयान में कहा कि 2013 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए, लेकिन इनमें कुछ ऐसे बदलाव भी थे जो महिलाओं और अन्य वर्गों की भागीदारी को कम करने वाले थे। अब पारित हुए वक्फ संशोधन विधेयक से वक्फ संपत्तियों को नए स्तर पर संरक्षण और पारदर्शिता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का एक प्रमुख उद्देश्य निजी ट्रस्टों को वक्फ से अलग करना है ताकि वक्फ संपत्तियों का स्वतंत्र और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन कर उन्हें केंद्रीय वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में लाया जाएगा जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी। डॉ. बिंदल ने बताया कि पारिवारिक वक्फ में महिलाओं को उचित अधिकार देने और संपत्तियों की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की आमदनी निरंतर घट रही है जिससे धार्मिक और सामाजिक कल्याणकारी कार्यों में बाधा आ रही है। इस विधेयक के माध्यम से किराए और आमदनी की वसूली को सख्ती से लागू किया जाएगा जिससे वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधार के रूप में लाया गया है। इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों का संरक्षण और उनके सही उपयोग को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से वक्फ बोर्ड और मुस्लिम समुदाय को ही सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

हिमाचल में चढ़ा पारा, आज बारिश-बर्फबारी की संभावना

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

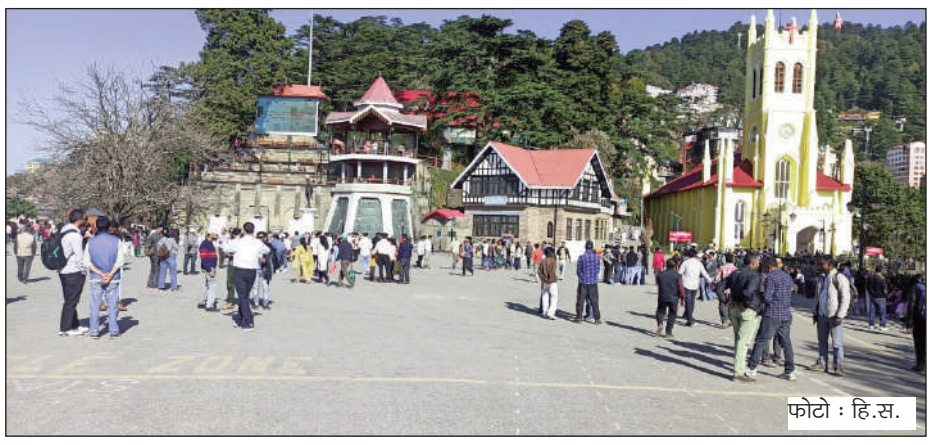
फोटो : हि.स.

हिमाचल प्रदेश में लगातार तेज धूप के कारण तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का असर तेज होने लगा है वहीं पहाड़ी इलाकों में भी ठंडक कम होती जा रही है। मंगलवार को राज्य में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जिससे गर्मी का अहसास बढ़ गया।

प्रदेश के मैदानी जिलों में धूप का असर साफ देखा जा सकता है। आज भी पूरे राज्य में तेज धूप खिली हुई है जिससे तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं पहाड़ी इलाकों में सुबह-शाम की ठंडक धीरे-धीरे कम हो रही है। हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी सर्दी का प्रभाव जारी है और यहां का तापमान शून्य के करीब बना हुआ है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पूवार्नुमान जारी करते हुए बताया कि 3 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। खासतौर पर लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा जिले के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। हालांकि 4 से 7 अप्रैल तक मौसम साफ बना रहेगा, जिससे तापमान में और वृद्धि होगी और गर्मी का असर तेज होगा। लेकिन 8 अप्रैल को एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है।

बीते 24 घंटों में राज्य के औसतन न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हिल स्टेशन शिमला की रातें मैदानी इलाकों से गर्म रहीं। बुधवार को शिमला में न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मैदानी क्षेत्रों सुंदरनगर, ऊना, कांगड़ा और मंडी में यह क्रमशः 9.9 डिग्री, 7.9 डिग्री, 10.8 डिग्री और 11.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

लाहौल-स्पीति जिले का मुख्यालय केलंग राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य स्थानों की बात करें तो कुकुमसेरी में 2.8 डिग्री, कल्पा में 4 डिग्री, बरठीं में 7.1 डिग्री, सियोबाग में 7.5 डिग्री, सोलन में 7.5 डिग्री, भुंतर में 7.6 डिग्री, मनाली में 8.1 डिग्री, डलहौजी में 11.1 डिग्री और कुफरी में 8.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

छोटा शिमला में सड़क किनारे लगी लोहे की जाली चोरी

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

राजधानी के छोटा शिमला थाना क्षेत्र में लोहे की जालियों की चोरी का मामला सामने आया है। इस संबंध में स्थानीय निवासी पंच राम चौहान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।

शिकायत के अनुसार पंच राम चौहान निवासी विकास नगर शिमला ने हाल ही में छोटा शिमला-कुसुम्पटी सड़क के किनारे लोहे की जाली लगाने का कार्य करवाया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि 31 मार्च को उन्होंने सड़क किनारे जालियां लगवाई थीं। लेकिन जब वह अगले दिन सुबह करीब 6 बजे आयुर्वेदिक अस्पताल पहुंचे, तो देखा कि उनकी लगाई हुई 28 जालियां चोरी हो चुकी थीं।

इस घटना की सूचना मिलने के बाद थाना छोटा शिमला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) बीएनएस में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की प्रक्रिया जारी है।

जांच अधिकारी ने बुधवार को बताया कि जल्द ही चोरों का पता लगाया जाएगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चैत्र नवरात्रि में भक्तिमय हुआ मां वैष्णो देवी धाम, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां वैष्णो देवी धाम पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। भवन परिसर, यात्रा मार्ग और आधार शिविर कटड़ा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्तजन मां के जयकारे लगाते हुए टोलियों में माता के दरबार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं जिससे भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो।

मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और बिना आरएफआईडी यात्रा कार्ड के यात्रा की अनुमति नहीं है। इसको लेकर श्राइन बोर्ड ने कटड़ा में सभी पंजीकरण केंद्रों को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है। ये केंद्र सुबह 4:00 बजे से रात 10:00 बजे तक खुले रहते हैं जहां श्रद्धालु आसानी से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। कटड़ा के मुख्य बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस अड्डा, निहारिका भवन और कटड़ा हेलीपैड सहित विभिन्न स्थानों पर यात्रा पंजीकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा रात के समय ऑनलाइन पंजीकरण करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन ड्योढ़ी और ताराकोट मार्ग के प्रवेश द्वार पर भी पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालु अपने अनुसार विभिन्न तरीकों से यात्रा कर रहे हैं। कुछ भक्त लेटकर या दंडवत प्रणाम करते हुए यात्रा कर रहे हैं जबकि अन्य पैदल, घोड़े, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर और रोपवे का सहारा ले रहे हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तों की भक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्राइन बोर्ड ने सभी सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किया है। इनमें घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा और भवन से भैरव घाटी तक चलने वाली रोपवे केबल कार सेवा शामिल हैं। मौसम भी साफ रहने से श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने यात्रा के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्ग को छह सेक्टरों में विभाजित किया गया है जिनमें कटड़ा आधार शिविर, बाणगंगा, अर्धकुंवारी, सांझीछत, हिमकोटी और भवन परिसर शामिल हैं। हर सेक्टर में श्राइन बोर्ड के डिप्टी सीईओ स्तर के अधिकारी और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद बनी रहे। भवन परिसर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए भवन परिसर में लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो भक्त मां वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं, वे कटड़ा की ओर प्रस्थान करें ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और बाकी श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन का अवसर मिले। चैत्र नवरात्रि के पहले तीन दिनों में सवा लाख से अधिक श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं। प्रतिदिन 45,000 से 50,000 श्रद्धालु यात्रा के लिए कटड़ा पहुंच रहे हैं। पहले नवरात्रि (30 मार्च) को 48,802 श्रद्धालु पहुंचे, दूसरे नवरात्रि (31 मार्च) को 45,780 भक्तों ने दर्शन किए, तीसरे नवरात्रि (1 अप्रैल) को शाम 4 बजे तक 24,800 से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके थे और यह संख्या लगातार बढ़ रही थी।

चैत्र नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और भक्तिमय माहौल ने मां वैष्णो देवी धाम को पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए बेहतर प्रबंधों के चलते यात्रा सुगम बनी हुई है।

संक्षिप्त-समाचार

जम्मू-कश्मीर ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना में किया संशोधन

जम्मू। जम्मू और कश्मीर सरकार ने आपदा प्रबंधन नियम, 2007 के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। एक आदेश के अनुसार प्राधिकरण में अब मुख्यमंत्री अध्यक्ष (पदेन) के रूप में, उपमुख्यमंत्री उपाध्यक्ष के रूप में और स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, जल शक्ति, कृषि उत्पादन और खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पदेन) के रूप में कार्य करेंगे जबकि आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग के प्रशासनिक सचिव सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

कठुआ के पंचतीर्थी में ड्रोन और चापर की मदद से चलाया जा रहा तलाशी अभियान

जम्मू। जिला कठुआ के पंचतीर्थी के जंगल में सुरक्षाबलों का तलाशी अभियान बुधवार को भी जारी है। इस अभियान में सुरक्षाबल हेलीकॉप्टर, ड्रोन व खोजी कुत्तों की भी मदद ले रहे हैं। सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र में घेर रखा है । इससे पहले आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच सोमवार रात को शुरू हुई मुठभेड़ मंगलवार शाम तक जारी रही और दोनों तरफ से रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही। इस दौरान जंगल क्षेत्र में स्थित पंचतीर्थी मंदिर की दीवार और एक पिल्लर को भी गोली लगी है। कल शाम साढ़े छह बजे के बाद से गोलीबारी बंद है पर ऑपरेशन जारी है। हालांकि कल एक आतंकी के मारे जाने व एक के घायल होने की सूचना आई थी लेकिन अभी तक किसी का शव बरामद नहीं हो पाया है।

पीएनबी मेटलाइफ में अप्रेंटिस पदों के लिए साक्षात्कार 4 को

ऊना। पीएनबी मेटलाइफ ऊना में अप्रेंटिसशिप के लिए 35 पदों की आवश्यकता है। इन पदों के लिए साक्षात्कार 4 अप्रैल को सुबह 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना में आयोजित किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन, आयु सीमा 21 से 35 वर्ष और वेतन 15 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपने योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, हिमाचली बोनाफाइड, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार की फोटो, मूल प्रमाण पत्र, बायोडाटा की कॉपी और अनुभव प्रमाण पत्र सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।

फ्री टैली कोर्स सीखने को 7 से पहले करें अप्लाई

ऊना। आरसेटी ऊना के निदेशक पारुल विरदी ने जानकारी दी कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) में 8 अप्रैल से कंप्यूटर अकाउंटिंग एवं टैली, ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट में प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। यह प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा और 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और 3 पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य रहेगा। आरसेटी के निदेशक ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा रहेगी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अभ्यर्थियों प्रशिक्षुओं को सरकारी पंजीकृत प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण लेने के भी पात्र होते हैं। उन्होंने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थियों को 7 अप्रैल तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

राजौरी में एक ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त

राजौरी। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में अधिकारियों ने बुधवार को एक ड्रग तस्कर की अचल और चल संपत्ति जब्त की। अधिकारियों ने बताया कि राजौरी तहसील के हारून रशीद के स्वामित्व वाली आवासीय और व्यावसायिक इमारतों और एक कार को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस), 1985 की धाराओं के तहत जब्त कर दिया गया है। क्षेत्र में मादक पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत यह कार्रवाई की गई। हारून रशीद ड्रग तस्करी के कई मामलों में शामिल है।

जम्मू-कश्मीर में 4 से 7 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना

श्रीनगर। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने आज पूवार्नुमान लगाया है कि 2 अप्रैल को मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहेगा जबकि 3 अप्रैल को उत्तरी कश्मीर और सोनमर्ग-जोजिला अक्ष के ऊंचे इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बर्फबारी की संभावना है। 4 से 7 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, उसके बाद 8 अप्रैल को बादल छाए रहेंगे और हल्की बर्फबारी की संभावना है। 9 और 10 अप्रैल को कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग के अलग-अलग इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी के साथ मौसम बादल छाए रहने का अनुमान है। 11 अप्रैल को सुबह के समय मौसम बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है उसके बाद मौसम में सुधार होगा।

कठुआ के पंचतीर्थी में ड्रोन और चापर की मदद से चलाया जा रहा तलाशी अभियान

जम्मू। जिला कठुआ के पंचतीर्थी के जंगल में सुरक्षाबलों का तलाशी अभियान बुधवार को भी जारी है। इस अभियान में सुरक्षाबल हेलीकॉप्टर, ड्रोन व खोजी कुत्तों की भी मदद ले रहे हैं। सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र में घेर रखा है । इससे पहले आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच सोमवार रात को शुरू हुई मुठभेड़ मंगलवार शाम तक जारी रही और दोनों तरफ से रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही। इस दौरान जंगल क्षेत्र में स्थित पंचतीर्थी मंदिर की दीवार और एक पिल्लर को भी गोली लगी है। कल शाम साढ़े छह बजे के बाद से गोलीबारी बंद है पर ऑपरेशन जारी है।

शिलाई में 19 करोड़ की लागत से बनेगा 100 बिस्तरों का अस्पताल, उद्योग मंत्री ने किया भूमि पूजन

नाहन। जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उद्योग, संसदीय मामले एवं श्रम रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज 100 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल भवन का भूमि पूजन किया। यह अस्पताल 19 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होगा और जल्द ही क्षेत्रवासियों को समर्पित किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दूरदराज के इलाकों में अस्पतालों के ढांचागत विकास और स्टाफ की उपलब्धता को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के बनने से क्षेत्र के मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर किए बिना स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। मंत्री ने यह भी बताया कि नागरिक अस्पताल शिलाई में जल्द ही विशेषज्ञ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरा जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि हाल ही में 25 लाख रुपये की लागत से डिजिटल एक्स-रे प्लांट का लोकार्पण किया गया है, जिससे अब अस्पताल में रंगीन एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि शिलाई क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा सुधार किया गया है। क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में लगभग 300 रिक्त पदों को भरकर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। मंत्री ने कहा कि शिलाई अब तेजी से विकसित होते हुए शहर का रूप ले रहा है, जिसके चलते इसे नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। इसके तहत 68 करोड़ रुपये की डीपीआर स्वीकृति हेतु भेजी गई है, जिसमें 28 करोड़ रुपये सीवरेज सिस्टम के लिए, 30 करोड़ रुपये पानी और अन्य सुविधाओं के लिए प्रस्तावित हैं। उन्होंने बताया कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र में सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये की विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र के लोगों को व्यापक लाभ मिलेगा। इसके बाद, उद्योग मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के शिलाई विश्राम गृह में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मार्केटिंग कमेटी के अध्यक्ष सीता राम शर्मा, निदेशक एचपीएसआईडीसी रमेश देसाई, पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रताप सिंह तोमर व रंजीत नेगी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरी राम शास्त्री, और विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का

नवोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: सतपॉल शर्मा

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक भुपेंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1 सेक्टर-40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित- 160036

सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।

स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

लोग दिल खोलकर करेंगे प्रधानमंत्री का स्वागत: नायब सैनी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समालखा स्थित सेवा साधना केंद्र में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में पहुंचे

संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को समालखा स्थित सेवा साधना केंद्र में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए जानकारी दी कि आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को दो बड़ी सौगातें देंगे जिसमें हिसार स्थित एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और यमुनानगर में 800 मेगावाट बिजली की यूनिट का शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री का दिल खोलकर स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व स्तर पर भारत की पहचान को मजबूत किया है और एक विजन लेकर विकसित भारत के मिशन में लगे हैं। प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार विकसित भारत विकसित हरियाणा की तर्ज पर तीन गुना तेजी से विकास कार्यों को कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कार्यक्रम की तैयारी और व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। आगामी 5 तारीख को रोहतक में प्रदेश के सभी मंत्रियों, विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित कर पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बिल पेश करने जा रही है जिसके लागू होने से वक्फ बोर्ड को लेकर कोई भी डिस्प्यूट नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने मंडियों में फसलों की आवक को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। फसल की आवक को लेकर मंडियों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 48 घंटे में उठान करवाना सुनिश्चित करें

- प्रदेश को डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती पर मिलेंगी दो बड़ी सौगातें
- हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ-साथ यमुनानगर में 800 मेगावाट की यूनिट का प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास

और निश्चित अवधि में किसानों के खाते में फसल का पैसा भी भेजना सुनिश्चित करें। अधिकारी मंडियों में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नवरात्रों की बधाई दी और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा व अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी सहित अन्य गणमान्य मौजूद थे।

डिजिटल शिक्षा और पुस्तकालय संसाधनों की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठी का किया आयोजन

अनिल गोयल
लाडवा

इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज, लाडवा में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के अवसर पर ॽपुस्तकालय संसाधनों, सहित कॉलेज पुस्तकालय द्वारा सब्सक्राइब किए गए ई-संसाधनों के उपयोगॽ विषय पर एक संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. कुशल पाल और लाइब्रेरियन डॉ. रूपेश गौड़ के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

प्राचार्य डॉ. कुशल पाल ने छात्रों को पुस्तकों का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मोबाइल युग में छात्रों में घटती पढ़ने की आदतों पर चिंता व्यक्त की और उन्हें अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने का आग्रह किया।इस कार्यक्रम का उद्देश्य ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (डएफ) और एनलिस्ट (ठछक्रळ), ठउछक ई-पीजी पाठशाला, ई-ज्ञानकोश तथा अन्य निःशुल्क शैक्षिक संसाधनों के बारे में छात्रों को जागरूक करना और उनकी शैक्षिक व अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना था। इस संगोष्ठी में कुल 50 छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और डिजिटल लर्निंग टूल्स को सीखने में उत्सुकता दिखाई। कॉलेज लाइब्रेरियन डॉ. रूपेश गौड़ ने पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं पर प्रकाश डाला और बताया कि छात्र ई-संसाधनों का उपयोग अपनी पढ़ाई और व्यावसायिक विकास के लिए कैसे कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों से केवल प्रामाणिक (ॅ३ौल्ल३ू) सामग्री का उपयोग करने का अनुरोध किया और डिजिटल युग में प्रामाणिक सामग्री की बढ़ती आवश्यकता पर अपनी चिंता व्यक्त की। रसायनशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार ने भी छात्रों को पुस्तकालय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने डिजिटल ज्ञान प्लेटफार्मों का नियमित उपयोग करने और बेहतर करियर अवसरों के लिए इसे अपनी आदत में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में डॉ. नीतू, डॉ. वंदना, डॉ. प्रियंका, किरण देवी, करिश्मा और सचिन सहित कई संकाय सदस्य भी उपस्थित रहे।

हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व लक्ष्य को किया हासिल

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व संग्रहण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अपने बजट लक्ष्य को हासिल कर लिया है। विभाग ने 61,950 करोड़ रुपये के आवंटित लक्ष्य की तुलना में 63,371 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक एकत्रित किए हैं, जो निर्धारित लक्ष्य का 102.3 प्रतिशत है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एसजीएसटी संग्रह 39,153 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो 37,500 करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य से अधिक है और पिछले वर्ष (सेस को छोड़कर) की तुलना में 13.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। इसी तरह, उत्पाद शुल्क

संग्रह 12,701 करोड़ रुपये रहा, जो 12,650 करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य से अधिक है और पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि इस बीच, वैट और सीएसटी संग्रह 11,517 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के आंकड़ों से 1.6 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि राजस्व सृजन में यह उत्कृष्ट प्रदर्शन कुशल कर प्रशासन, नीतिगत सुधारों और आर्थिक विकास के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में नगर निगम और बिजली विभाग की संयुक्त बैठक संपन्न

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों के विकास और जनकल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में और अधिक तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे। विपुल गोयल ने आज फरीदाबाद विधानसभा के समस्त नवनिर्वाचित पार्षदों, नगर निगम अधिकारियों एवं बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक में विपुल गोयल के साथ खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री राजेश नागर भी उपस्थित रहे। इस महत्वपूर्ण बैठक का उद्देश्य सभी विभागों और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था, ताकि वार्डों के विकास कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके और फरीदाबाद के नागरिकों को उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

विपुल गोयल ने नगर निगम और बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पार्षदों के साथ तालमेल बनाकर कार्य करें और किसी भी विकास परियोजना को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जो भी विकास कार्य वर्तमान में चल रहे हैं, उन्हें तय समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। यदि किसी भी कार्य में अनावश्यक देरी होती है, तो इसे संबंधित अधिकारी की लापरवाही मानी जाएगी और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि जल निकासी व्यवस्था को समय रहते दुरुस्त किया जाए, ताकि बरसात के दौरान लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस संदर्भ में उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नालों और सीवर लाइनों की सफाई का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए और नियमित रूप से इसकी निगरानी की जाए। उन्होंने जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी समीक्षा की और सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे मिलकर कार्य करें, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएँ मिल सकें। विपुल गोयल ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी गर्मी और मानसून से पहले ही सभी आवश्यक तैयारियाँ कर लें, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक उपकरणों को रिपेयर स्टोरेज में उपलब्ध रखा जाए और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि नागरिकों को परेशानी न हो।

संक्षिप्त-समाचार

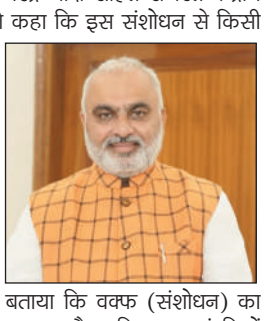

वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर जगमोहन आनंद ने प्रधानमंत्री का जताया आभार

करनाल। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास होने पर करनाल विधायक जगमोहन आनंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित समस्त केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है यह सबके हितों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा में पारित हो गया है। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। विधायक जगमोहन आनंद ने बताया कि लोकसभा में इस विधेयक को पूर्ण बहुमत से पारित किया गया है। यह सभी मुसलमानों के पूर्णत पक्ष में हैं। उन्होंने बताया कि वक्फ (संशोधन) का उद्देश्य पिछले वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। संशोधन विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलने, वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करने, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करने और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ाना है। विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि इस बिल में संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करना है, जो औपनिवेशिक युग का कानून है जो आधुनिक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए पुराना और अपर्याप्त हो गया है।

सड़कों की मरम्मत के लिए बनाई खास योजना : रणबीर गंगवा

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा की सड़कों की मरम्मत के लिए विभाग ने खास योजना बनाई है। अगले 6 महीनों में इस पर विशेष कार्रवाई होगी , साथ ही प्रदेश की सड़कों के जाल को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि आमजन के लिए बेहतर और सुगम सफर हो सके। रणबीर गंगवा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत आने वाली करीबन 6300 किलोमीटर सड़कों की रिपेयरिंग का कार्य इस अवधि के दौरान करने का एक्शन प्लान बनाया है। विशेष टेंडर के जरिए काम होगा।

उल्लेखनीय है कि बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में घोषणा की थी कि आगामी 6 महीने के अंदर-अंदर सभी सड़कों की आवश्यकता अनुसार मरम्मत करवाई जाएगी। गंगवा ने विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की

घोषणा को धरातल पर लाने के लिए खास योजना तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है, विभाग के प्रयास है कि जनता को बेहतर और उच्च क्वालिटी की सड़कें मिले। विभाग के अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए है कि क्वालिटी में किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। उन्होंने गर्मी के मौसम में पेयजल को लेकर की जाने वाली तैयारियों के बारे में कहा कि इसे लेकर भी तैयारियां पूरी हैं, संबंधित विभाग के अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए जा चुके है।

गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है, सरकार का यही प्रयास है कि ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे जनता को फायदा हो। चंडीगढ़ सचिवालय में बुधवार को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा तथा सदस्य शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की अध्यक्षता में हुई विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) की बैठक में 3 एजेंडे रखे गए थे।

बैठक में ब्लीचिंग पाउडर, पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड एवं स्टेनलैस स्टील स्कीन परचेजिंग को लेकर प्रक्रिया में शामिल हुई कंपनियों से कमेटी ने बातचीत की। इस दौरान पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड एवं स्टेनलैस स्टील स्कीन के 4.41 करोड़ के 2 एजेंडे स्वीकृत किए गए। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यही है कि उच्च क्वालिटी की सुविधा जनता को मिले।

स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और हरियाणा में स्वास्थ्य परियोजनाओं से संबंधित चर्चा की। इस अवसर पर केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन , योजना तथा कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी साथ थे।

कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने आशीर्वाद लिया और प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में सहयोग बढ़ाने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री को उन्होंने अवगत करवाया कि वर्ष 2015 में उन्होंने पानीपत से ॽबेटी बचाओ बेटी पढ़ाओॽ अभियान की जो शुरूआत की गई थी उस वक्त हरियाणा में लिंगानुपात 1000 लड़कों की तुलना में मात्र 871 था , लेकिन प्रधानमंत्री के आह्वान और हरियाणा सरकार के प्रयासों की बदौलत अब यह लिंगानुपात 910 तक पहुँच गया है। अब प्रदेश सरकार इस अनुपात को समान करने के लिए गहन प्रयास कर रही है।

बाद में मीडिया से बातचीत में कुमारी आरती सिंह राव ने कानून बनाकर केंद्र सरकार द्वारा नए वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल किये जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने बताया कि अब वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी और महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ का मामला धर्म से नहीं, बल्कि संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा है इसमें गरीब तबके के लोगों और महिलाओं की भागीदारी से मुसलमान बहन-भाइयों के हित में कल्याणकारी कदम उठाने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताते हुए कहा कि मोदी जी देश के हर वर्ग की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री हैं , उन्होंने मुस्लिम समाज की बहनों को तीन तलाक के काले कानून से मुक्ति दिलाकर महिलाओं के मन से हमेशा के लिए बेवजह के ॽगुमानीॽ तलाक के डर को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं और गरीब वर्ग के सबसे बड़े हितैषी हैं।

हरियाणा के मुख्य सचिव ने सौ फीसदी आधार कवरेज पर बल दिया

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आज यहां विशिष्ट पहचान कार्यान्वयन समिति (यूआईडीआईसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेशभर में शत-प्रतिशत आधार की आवश्यकता पर बल दिया।

आधार पंजीकरण में तेजी लाने के लिए, रस्तोगी ने बैंकिंग और डाक विभाग समेत सभी विभागों को जल्द से जल्द आधार नामांकन किट्स की पूर्ण सक्रियता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, आधार सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर भी बल दिया।

उन्होंने निर्देश दिए कि छात्रों को आधार पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी और निजी स्कूलों में विशेष नामांकन शिविर आयोजित किए जाएं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने नागरिकों की डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए एम-आधार ऐप और माय-आधार पोर्टल को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। रस्तोगी ने निर्देश दिए कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर सभी माता-पिता से 5 और 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) पूरा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विभाग आधार केंद्रों और अन्य कार्यालयों में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लाभार्थियों का आधार आधारित प्रमाणीकरण सुनिश्चित करें। साथ ही, सभी सरकारी विभागों में आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण उपस्थिति प्रणाली भी लागू की जाए।

बैठक के दौरान, चंडीगढ़ स्थित यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय की उप-महानिदेशक श्रीमती भावना गर्ग ने 0-5 वर्ष की आयु के बच्चों में आधार नामांकन बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के लिए पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच सहयोग से टीकाकरण केंद्रों पर आधार किट तैनात करने का प्रस्ताव रखा।

कार्यक्रम के लिए उपलब्ध मंच संविधान, संगम, जहां से हरियाणा के भविष्य निर्माण का बुना जाता है सपना: डॉ. मिड्ढा

हरियाणा युवा संवाद समारोह भविष्य की नीतियों की प्रयोगशाला

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा ने राजधानी युवा संसद द्वारा हरियाणा विधानसभा सदन में हरियाणा युवा संवाद, 2025 कार्यक्रम के आयोजन के लिए संस्था से जुड़े सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा का चयन किया है। दो दिवसीय हरियाणा युवा संवाद का शुभारंभ करने उपरांत अपने संबोधन में डॉ. मिड्ढा ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हरियाणा के उपाध्यक्ष होने के नाते देश के कोने –कोने से चयनित प्रतिभाशाली युवाओं को मुझे इस महान सदन में संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह मंच न केवल विचार–विमर्श का स्थल है बल्कि भविष्य की नीतियों की प्रयोगशाला है। उन्होंने कहा कि जहां यह सम्मेलन हो रहा है यह कोई साधारण मंच नहीं बल्कि यह संविधान, संवाद और संवेदना का संगम है। उन्होंने कहा कि जहां राज्य के भविष्य निर्माण का सपना बुना जाता है और उसे पूरा किया जाता है। उन्होंने कहा कि तीन चरण के दौर से चयनित होकर हरियाणा विधानसभा सदन में 60 से अधिक युवा भाग ले रहे हैं जो न केवल अपने विचार सांझा करेंगे बल्कि समाज को किस प्रकार की दिशा देनी है और एक युवा अपने मन में इस बारे में क्या सोच रखता है वो इस मंच के माध्यम से हमारे सामने आएगी। डॉ. मिड्ढा ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि चर्चा के लिए डिजिटल माध्यम से हरियाणा में विकास और विस्तार तथा हरियाणा राज्य और महिला सशक्तिकरण दो विषय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर डिजिटल हरियाणा की बात करें तो हमे एक बात पर ध्यान देना होगा कि अगर दुनिया बदलनी है तो की–बोर्ड के साथ सोच भी बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि आज का भारत युवा भारत है। युवाओं में जोश है और कुछ करने को तैयार हैं। युवा का अगर हम उल्टा करें तो वह वायु बनता हैं और वायु कितनी तेज गति से चलती है, वह हम सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरियों के पीछे भागने वाला नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाला बनना होगा। युवाओं को क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर शिकायत ही करेंगे या समाज को बदलने के लिए आगे भी आएंगे। डॉ. मिड्ढा ने कहा कि 21वीं सदी की पहचान सिर्फ तकनीक के प्रति सोच से होती है। आज किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच ऑनलाइन करवा रहा है। दूर–दराज के गांव में बैठा एक विद्यार्थी विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। एक महिला उद्यमी ऐप के माध्यम से अपना रोजगार चला रही है। हमें आज तकनीकी, डिजिटल, प्रशासनिक कौशल चाहिए। आज हमें ऐसी नीति चाहिए जो समावेशी हो, न्यायसंगत हो और दूरदर्शी हो। इन्हीं के संतुलन से हरियाणा का नया स्वरूप उभरेगा। सोशल मीडिया पर भय से ज्यादा

समाज में समस्याओं का समाधान करने का कारक बने। यह डिजिटल हरियाणा की हकीकत बन सकती है अगर इस मंच पर उपस्थित आप जैसे युवा इस बदलाव के वाहक बने। डॉ. मिड्ढा ने कहा कि हरियाणा संवाद का दूसरा विषय है कि हरियाणा राज्य महिला सशक्तिकरण बहुत ही स्टीक विषय है क्योंकि अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो हमे यह बात याद रखनी होगी कि जहां नारी को अवसर मिलता है वहां सिर्फ घर नहीं पूरा राष्ट्र सशक्त होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की उन्नति तब तक संभव नहीं जब तक उसकी नारी शिक्षित, सुरक्षित और सशक्त न हो। हरियाणा युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में पहुंची कांग्रेस की विधायक श्रीमती गीता भुक्कल ने कहा कि युवा देश का उज्जवल भविष्य है। एक समय था जब साक्षर, ज्ञान को बढ़ाने के लिए साक्षरता मिशन चलाया गया। आज हम ई–गवेर्नेंस के युग में है। फिर भी हम ई–इलीट्रेट युवाओं को ई–पोर्टल के माध्यम से ई–गवेर्नेंस से विश्व की डिजिटल डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है। लोकतंत्र में विधायी पालिका को कानून बनना ब्यूरोक्रेसी को कानूनों को क्रियान्वित करवाना तथा न्यायपालिका को इन कानूनों का लोगों को न्याय देना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भी एक शैडो कैबिनेट होती है जो सत्र के दौरान विभिन्न जनहित के मुद्दे उठाकर सरकार को सचेत करती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज ई–कंटेंट के रूप में विषय –वस्तु उपलब्ध है। हमें इसे अपडेट रहना चाहिए। आज एआई का युग आ गया है आज दुनिया ई–विश्व बन गई है। उन्होंने विधानसभा कार्यवाही के प्रक्रिया के बारे भी युवाओं को विस्तृत जानकारी दी।

संपादकीय

भारत–चीन संबंधों की सच्चाई: सहयोग या टकराव?

भारत और चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, इन दोनों देशों के आपसी संबंधों का मूल्यांकन करना न केवल आवश्यक है बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। यह द्विपक्षीय संबंध अत्यंत जटिल हैं और ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों से प्रभावित हैं। समय-समय पर टकराव और प्रतिस्पर्धा के बावजूद, दोनों राष्ट्र व्यापार, बहुपक्षवाद और सांस्कृतिक साझेदारी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। चीन द्वारा दिए गए एलीफेंट-ड्रैगन डुएट के प्रतीकात्मक संदर्भ को देखते हुए, भारत और चीन को शांति, सहयोग और सह-अस्तित्व के सिद्धांतों पर आधारित आपसी संबंधों को विकसित करने की आवश्यकता है। आइये समझते हैं भारत-चीन संबंधों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में। भारत और चीन के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1950 में स्थापित हुए थे। पंचशील समझौता (1954) इन संबंधों की नींव बना, जिसमें शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांतों पर बल दिया गया था। प्रारंभिक वर्षों में दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहे, लेकिन 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद यह संबंध तनावपूर्ण हो गए। इसके बाद दशकों तक आपसी अविश्वास बना रहा। 1988 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के बाद, द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया शुरू हुई। विभिन्न स्तरों पर वाताएँ आयोजित की गईं, जिनमें व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। 2024 के इफ्कठ्र कजान शिखर सम्मेलन में भारत और चीन ने सहयोग को बढ़ाने का संकेत दिया। भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध बेहद गहरे हैं। 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापारिक लेन-देन 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, जबकि भारत को चीन के साथ बड़े व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। भारत, चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल कंपोनेंट्स, और मशीनरी का आयात करता है, जबकि लौह अयस्क, जैविक रसायन और अन्य कच्चे माल का निर्यात करता है। हालाँकि, चीन द्वारा दी जाने वाली सस्ती कीमतों के कारण भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की चुनौती बनी रहती है। चीन का भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी बड़ा निवेश है। 2020 तक, चीन ने भारतीय स्टार्टअप्स में 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया था। हालाँकि, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए चीनी निवेश पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंध हजारों वर्षों पुराने हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार में चीन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रसिद्ध चीनी यात्री नसांग और फाह्यान ने भारत की यात्रा की थी और यहाँ की संस्कृति को अपने देश में पहुँचाया था। वर्तमान समय में भी, चीन में योग, आयुर्वेद और भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की लोकप्रियता बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी सहयोग देखा जा रहा है। गर हम दोनों देशों भारत-चीन सुरक्षा और रणनीतिक संबंधों की बात करें तो भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जो अभी तक स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं हुई है। चीन, अक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा जमाए हुए है और अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। भारत, चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा निर्माण को संदेह की दृष्टि से देखता है। हालाँकि, मार्च 2025 में दोनों देशों के बीच 33वें कार्य तंत्र की बैठक हुई, जिसमें सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति बनी। भारत और चीन विभिन्न बहुपक्षीय मंचों—ब्रिक्स, एस सी ओ, जी20, और ए आई आई बी—में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। हालाँकि, भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बी आर आई का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि इसका एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत-चीन संबंधों में कई प्रमुख चुनौतियाँ भी हैं जैसे एल ए सी पर चीन द्वारा लगातार घुसपैठ और सैन्य तैनाती से तनाव बढ़ रहा है। गलवान घटना (2020) के बाद विश्वास बहाली एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 2023-24 में 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। चीन से महत्त्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादों की अधिक निर्भरता चिंता का विषय बनी हुई है। चीन द्वारा पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक सहायता देने से भारत की सुरक्षा चिंताएँ बढ़ती हैं। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भारत की संप्रभुता के लिए चुनौती बना हुआ है। चीन समर्थित साइबर समूहों द्वारा भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए हैं। भारत ने सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए 300 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों पर बनाए जा रहे बाँध भारत के जल संसाधनों के लिए खतरा हैं। भारत को चीन के साथ जल-सहयोग समझौतों पर ध्यान देना आवश्यक है। भारत-चीन संबंधों को सुधारने के लिए कई उपाय किये जा सकते हैं इनमें उच्च स्तरीय बैठकों और विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता को जारी रखना आवश्यक है। सीमा विवाद को हल करने के लिए निरंतर संवाद और सैन्य वार्ता आवश्यक हैं। भारत को चाइना प्लस वन रणनीति अपनाकर आपूर्ति श्रृंखला को विविधतापूर्ण बनाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। एल ए सी पर भारत को सैन्य बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना होगा। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए नीतिगत कदम उठाने होंगे। भारत को कुएड, एसिआन और बीमस्टैक जैसे मंचों पर अपनी भागीदारी को और मजबूत करना होगा। वैश्विक स्तर पर भारत को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से तैयार रहना होगा। अंत में कह सकते हैं कि भारत और चीन के संबंध द्विपक्षीय और वैश्विक राजनीति के महत्त्वपूर्ण कारक हैं। इन संबंधों में चुनौतीपूर्ण तत्व मौजूद हैं, लेकिन आपसी संवाद, रणनीतिक धैर्य, और आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से इन चुनौतियों को कम किया जा सकता है। यदि दोनों देश शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और बहुपक्षीय सहयोग को प्राथमिकता दें, तो एशिया और संपूर्ण विश्व को स्थिरता और समृद्धि की ओर अग्रसर किया जा सकता है।

आज का राशिफल

मेष: आज पुराने दोस्तों से बातचीत हो सकती है। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संतान की उन्नति से खुशी मिलेगी, लेकिन उन पर अत्यधिक दबाव न डालें। आत्मविश्लेषण के लिए समय मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य किसी कारणवश टल सकते हैं।

वृषभ: आमदनी में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। रुके हुए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। जीवनसाथी को करियर में सफलता मिलने की संभावना है। मानसिक शांति बनी रहेगी। खानपान में शुद्धता बनाए रखें और आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित रहेंगे।

मिथुन: आज आपको अपनी प्रतिष्ठा की चिंता रहेगी। लंबी यात्रा से बचें, क्योंकि स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कफ और सर्दी से परेशानी हो सकती है। बिना मांगे सलाह न दें। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से बहस न करें।

कर्क: अचल संपत्ति प्राप्त होने के योग हैं। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे सफलता मिलेगी। साझेदारी में किए गए व्यवसाय में लाभ की संभावना है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। बेरोजगारों के लिए नौकरी के अच्छे अवसर आ सकते हैं।

सिंह: कार्यस्थल पर आप विरोधियों पर हावी रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। महंगे सामान की खरीदारी संभव है। वैवाहिक जीवन में आपसी सम्मान बढ़ेगा। परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे। नए कार्यों में रुचि लेंगे और व्यवसाय में अनुकूलता बनी रहेगी।

कन्या: व्यवसाय में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, जिससे करियर में प्रगति होगी। आध्यात्मिक विचारों से मन को शांति मिलेगी। शेयर बाजार में निवेश लाभकारी हो सकता है। छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बौद्धिक चचाओं में भाग लेंगे।

तुला: गर्म और ठंडे खाद्य पदार्थों से बचें, अन्यथा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। धन हानि की आशंका है, इसलिए आज उधार लेन-देन से बचें। छोटी-छोटी बातों पर परेशान न हों, वरना जरूरी कार्यों से ध्यान भटक सकता है। अपच और गैस की समस्या हो सकती है।

वृश्चिक: अपने खानपान की आदतों पर नियंत्रण रखें। कार्यस्थल पर सभी कार्य आपकी योजनाओं के अनुसार पूरे होंगे। जीवनशैली बेहतर बनी रहेगी। व्यवसाय में प्रगति से संतुष्टि मिलेगी। मनोरंजन पर खर्च कर सकते हैं। आर्थिक तंगी से राहत मिलने की संभावना है।

धनु: संतान के भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है। भाई-बहनों के साथ संबंधों में तनाव महसूस करेंगे। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें। युवा अपने करियर को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। सहकर्मियों की मदद से धन लाभ होगा, लेकिन आत्मनिर्भरता बनाए रखना जरूरी है।

मकर: नई परियोजनाओं में धन निवेश कर सकते हैं। कानूनी मामलों को लेकर कुछ तनाव रहेगा। कॉलेज के विद्यार्थियों को नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में तनाव कम होगा। नई स्किल्स सीखने की रुचि बढ़ेगी, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी।

कुंभ: अनैतिक कार्यों से दूर रहें। किसी बात को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से नुकसान हो सकता है। दांपत्य जीवन में स्वार्थ की भावना न आने दें। करियर में नए प्रयोग करेंगे, लेकिन दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आवश्यक है।

मीन: व्यवसाय में आमदनी बढ़ने की संभावना है। परिवार के सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में प्रयासरत रहेंगे। अनुशासित दिनचर्या अपनाने से सफलता मिलेगी। योजनाबद्ध तरीके से काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है।

यमुना की सफाई और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की बड़ी चुनौती

27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 मार्च को बतौर वित्तमंत्री एक लाख करोड़ का बजट पेश करके अपनी सरकार के कामकाज की दिशा तय की। दिल्ली के लिए यह ऐतिहासिक बजट माना जा रहा है। बजट में उन सभी कामों के लिए आवंटन किया गया है, जिनके वायदे भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए थे। कुछ पर तो काम भी शुरू हो गया है और कुछ पर आने वाले दिनों में काम शुरू होने के संकेत हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले बजट से करीब 31.5 फीसदी की बढ़ोतरी की है और उनका दावा है कि इस वित्तीय साल में राजस्व भी 58,750 करोड़ रुपए के मुकाबले 68,000 करोड़ रुपए मिलने वाला है। वैसे तो हर काम में पैसे के साथ-साथ पूरी तैयारी और चौकसी जरूरी है लेकिन यमुना की सफाई के साथ-साथ पानी का संकट दूर करने और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की बहुत बड़ी चुनौती है। ये सभी काम केवल पैसे से न होंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान अन्य मुद्दों से ज्यादा ये दोनों मुद्दे प्रभावी रहे। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ यमुना की आरती में शामिल हुई और यमुना को साफ करने का संकल्प दोहराया। यमुना का पानी मानक के हिसाब से तो यमुनोत्री के आगे कुछ ही दूर तक साफ है लेकिन दिल्ली में पल्ला बांध (वजीराबाद) से ओखला यानी 22 किलोमीटर तो गंदे नाले से भी बदतर हाल में है। इसको साफ करने के नाम पर वर्षों से करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस सरकार ने बजट में यमुना की सफाई के लिए नौ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

यह वर्षों से प्रयास किया जा रहा है कि यमुना में गंदा पानी जाने से रोका जाए। यमुना को साफ कर उसे अहमदाबाद के सावरमती नदी की तरह विकसित की जाए। यमुना के किनारे कोयले बिजली बनाने वाले संयत्र सालों पहले बंद करा दिए गए। औद्योगिक कचरे या सीवर के गंदे पानी को साफ करने वाले संयंत्रों के माध्यम से साफ करके ही पानी यमुना में जाने दिया जाए। यमुना को प्रदूषित करने में अव्वल माने जाने वाले नजफगढ़ नाले में इंटरसेप्टर लगवाया गया। इस बजट में भी नए इंटरसेप्टर का प्रावधान किया गया है। 1994 में जब यमुना के पानी में दिल्ली को तब के मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना ने हिस्सा दिलाया था, तब दिल्ली का हरियाणा के साथ एक और समझौता हुआ था कि हरियाणा जितना पीने का पानी पल्ला बांध पर दिल्ली को देगा, दिल्ली उसे उतना ही पानी ओखला बांध पर सिंचाई के लिए देगी। अभी यमुना का पानी साफ होने को ही दिल्लीवासी सपना मान रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो दिल्ली पानी के मामले काफी आत्मनिर्भर हो जाएगी और यमुना साफ होकर दर्शनीय बन जाएगी।

यमुना सफाई जितना ही कठिन काम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त या यहां का प्रदूषण स्तर कम करना है। दिल्ली सरकार के बजट में इसको भी प्राथमिकता दी गई है। अलग-अलग तरीके से प्रदूषण नियंत्रित करने की बात कही गई है लेकिन बड़ी बात यह है कि सभी तरह के प्रदूषण (वायु, जल और हवा इत्यादि) के साथ-साथ कचरा और आपदा प्रबंधन के लिए एक ही जगह निगरानी व्यवस्था के लिए साझा केन्द्र (इंट्रीग्रेटेड कमान एंड कंट्रोल सेंटर) बनाने का प्रावधान किया गया है। कहने के लिए 1483 वर्ग किलोमीटर की दिल्ली है लेकिन एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के शहर दिल्ली से इस कदर जुड़े हुए हैं कि उन सभी को साथ लिए बिना कोई अभियान सफल नहीं हो सकता। केन्द्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के सभी पड़ोसी राज्यों, दिल्ली नगर निगम और दूसरी सरकारी एजेंसियों को साथ लेकर जनता की सक्रिय भागीदारी से इसका समाधान निकाला जा सकता।

यह साबित हो चुका है कि केवल आधे कारों को हर रोज सड़क पर

मनोज कुमार मिश्र (हि.स.)

आने से रोकने से वायु प्रदूषण में ज्यादा कमी नहीं आने वाली है। दूसरे, सरकारी कुव्यवस्था झेल रहे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली इस हालत में भी नहीं है कि दिल्ली सरकार इस तरह के प्रयोग बार-बार कर पाए। गिनती के बचे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और सरकार के अधीन चलने वाली बसों की तादाद तुरंत बढ़ानी होगी। इस बजट में सार्वजनिक परिवहन पर 12,952 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने बिजली से चलने वाली पांच हजार बसें तुरंत खरीदने का वायदा किया है।

दिल्ली के चारों ओर ईस्टर्न पेरिफेरियल और वेस्टर्न पेरिफेरियल सड़क बन जाने से दिल्ली होकर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले ट्रकों का दिल्ली के भीतर आना कम हुआ है। केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली के लिए 50 हजार करोड़ की परियोजना बनाई थी, इसमें ज्यादातर पूरे भी हो गए हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) समेत अनेक अदालतों ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बार-बार कड़े आदेश दिए हैं। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की एक बड़ी वजह पराली जलाना भी माना जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान खेत में फसलों के अवशेष जलाते हैं, जिसका धुंआ दिल्ली पर छा जाता है। अदालती आदेश के बाद सरकारों ने पराली न जलाने और पराली के दूसरे बेहतर उपयोग के प्रयास शुरू किए हैं। इसी तरह एनजीटी ने पेट्रोल से चलने वाली 15 साल पुरानी और डीजल से चलने वाली 10 साल पुरानी कारों पर पाबंदी लगा दी है। बावजूद इसके प्रदूषण कम होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली में पहले भी सारे व्यवसायिक वाहनों को अदालती आदेश से सीएनजी पर चलाया जा रहा है।

हालात एक दिन में खराब नहीं हुए हैं। कुप्रबंधन एवं सरकारी लापरवाही ने दिल्ली के हालात बदतर बना दिए और सुधार के आसार दिख नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 1998 को आदेश दिया कि दिल्ली में चलने वाली सभी बसों को धीरे-धीरे सीएनजी पर लाया जाए। इसकी तारीख 31 मार्च 2001 तय की गई। सरकारें एक- दूसरे पर जिम्मेदारी टालती रही तो अप्रैल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सख्त आदेश दिए। उसके बाद सीएनजी पर बसों और व्यवसायिक वाहनों को लाने की प्रक्रिया तेज हुई। कायदे में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में मिले पैसों से दिल्ली की सड़कों पर बसें दिखने लगी। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में 15 हजार बसें चलाने का हलफनामा दे रखा है लेकिन अब तो 2010 की बसें भी सड़कों से हटने लगी और बसों की संख्या गिनती की रह गई हैं। डीटीसी के अधीन चलने वाली निजी बसें ही सड़कों पर दिख रही है। दिल्ली मेट्रो अपनी गति से चल रही है। काफी लोग लोकल रेल से भी यात्रा करते थे, उसे भी अभी ठीक से शुरू नहीं किया गया है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की कमी के चलते जिसके लिए संभव है, वह अपने वाहन से यात्रा कर रहा है। ऐसे में सड़कों पर से वाहनों की भीड़ कम कैसे हो सकती है?

दिल्ली में पंजीकृत वाहनों की तादाद एक करोड़ से ज्यादा है। लाखों वाहन एनसीआर के दूसरे राज्यों में पंजीकृत हैं जो हर रोज दिल्ली में चलते हैं। इसलिए कोई भी योजना पूरे एनसीआर के लिए बनाने के बाद ही प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है। दिल्ली का न अपना मौसम है और न ही दिल्ली वालों की जरूरत पूरा करने के लिए बिजली और पानी। दिल्ली की किसी भी समस्या का समाधान करना अकेले दिल्ली के बूते नहीं है। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बेहतर हो ताकि सड़कों से निजी वाहनों की संख्या कम की जा सके। सड़कों को जाम से मुक्त करने के लिए ठोस प्रयास हो। दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों से प्रदूषण कम करने के मानकों पर अमल करवाया जाए। प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी उद्योग को दिल्ली में नहीं चलने दिया जाए। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण रोकने के मानकों पर कड़ाई से अमल हो। पर्यावरण को राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाए आम जन के जीवन बचाने का मुद्दा बनाया जाए।

इसी तरह आम भागीदारी और सरकारी तंत्र के प्रयास से यह सुनिश्चित करना होगा कि यमुना में एक बूंद भी गंदा पानी न जाए और उसमें किसी तरह का कूड़ा-कचरा डालने पर कठोर दंड दिया जाए। मूल समस्या दिल्ली की अनधिकृत कालोनी और अवैध निर्माण है, जिनमें से ज्यादातर में सीवर प्रणाली है भी नहीं जहां है भी वह कारगर नहीं है। वहां की गंदगी तो सीध यमुना में जा ही रही है। जिन इलाकों में दिल्ली बसने के समय सीवर लाइन डली थी, उनमें से ज्यादातर बेकार हो चूकि है। सीवर लाइनें जाम है उसमें बहाव के लिए जगह ही नहीं है। सीवर और पानी की मुख्य लाइनों को बदलने का काम काफी समय से चल रहा है सीवर की गंदगी और गंदा पानी पाइप के रास्ते जल शोधन यंत्रों के बजाए सड़कों और नालों से सीधे यमुना में जा रहा है। इसे कब और कैसे ठीक किया जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। प्रदूषण नियंत्र की तरह ही यमुना भी केवल पैसे के दम पर साफ नहीं हो सकती। सरकार की ताकत, मनसा और जन भागीदारी के बिना न तो दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो पाएगी और न ही यमुना नदी साफ।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार के कार्यकारी संपादक हैं।)

पेड़ काटना मानव हत्या के समान

अब यह समझ लेना जरूरी है कि कोई कानून और पेड़ों को हल्के में न ले। देश में लगातार जारी पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि एक पेड़ का कटना इंसान की हत्या से भी बदतर है। कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को नये पौधे लगाने की अनुमति तो दी, लेकिन काटे गए 454 पेड़ों के बदले प्रति पेड़ एक लाख रुपये के हिसाब से लगाया जुमार्ना कम करने से इनकार कर दिया। ऐसा कोर्ट ने अभियुक्त के गलती स्वीकारने और माफी मांगने के बावजूद किया।

इसके जरिये कोर्ट ने साफ संदेश दिया कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने स्पष्ट संदेश दिया कि संबंधित प्राधिकारी की आज्ञा के बिना पेड़ काटने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि ताजमहल व अन्य पुरातात्विक इमारतों के संरक्षण के लिये बनाये गए ताज ट्रेपोजियम क्षेत्र में 454 पेड़ कटवा दिए गए थे। दरअसल, कोर्ट ने इस मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में सहयोग कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एडीएन राव के इस सुझाव पर सहमति जतायी कि कोई कानून और पेड़ों को हल्के में न ले। वहीं, जुमार्ना लगाने के बाबत भी कोर्ट ने मानक तय किया कि इसमें किसी तरह रियायत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने इस

राकेश दुबे (हि.स.)

बात को लेकर भी चिंता जतायी कि जो पेड़ काटे गए हैं, उसकी जगह नये पेड़ लगाने के बावजूद इसकी क्षतिपूर्ति में सौ साल लग जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील संरक्षित ताज ट्रेपोजियम क्षेत्र में अदालत ने पेड़ काटने पर वर्ष 2015 से ही प्रतिबंध लगा रखा था। इसके बावजूद अदालत की अनुमति के बिना सैकड़ों पेड़ काट डाले गए। जिसके बाद न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति यानी सीईसी की वह रिपोर्ट स्वीकार कर ली कि बीते वर्ष 454 पेड़ काटने वाले व्यक्ति पर प्रति पेड़ के हिसाब से एक लाख रुपये का जुमार्ना लगाया जाए।

कोर्ट ने अभियुक्त की तरफ से पेश वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की वह दलील ठुकरा दी कि अभियुक्त ने गलती मानते हुए माफी मांग ली है, तो उसे जुमार्ना कम करके राहत दी जाए। हालांकि कोर्ट ने पास के किसी स्थान पर पौधरोपण करने की अनुमति जरूर प्रदान कर दी है।

ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान में निरंतर वृद्धि जारी है, वृक्षों का होना प्राणवायु का जरिया ही है। जो हमें शहरों के कंक्रीट के जंगल से उत्पन्न खतरों से बचाते हैं। खासकर पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाकों में उनकी दोहरी भूमिका है। ऐसे में नीति-नियंताओं को सोचना होगा कि कैसे किसी व्यक्ति को संवेदनशील इलाके में पेड़ काटने की अनुमति दी गई। निरंतर बढ़ते तापमान के दौर में वृक्षों के प्रति संवेदनशीलता शासन-प्रशासन के साथ समाज में भी होनी चाहिए। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन और राजस्थान में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिये लोगों के त्याग व संघर्ष को हमें याद रखना चाहिए। जनता का कड़ा प्रतिरोध भी वृक्षों की रक्षा करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

वक्फ विधेयक को समझना: मिथक बनाम उजागर किये गए तथ्य

वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ भ्रामक जानकारी फैलाने के अभियान का पर्दाफाश

कुछ राजनीतिक संस्थाओं और मुस्लिम समुदाय के भीतर निहित स्वार्थी समूहों द्वारा जानबूझकर अशांति का वातावरण बनाने के लिए भ्रामक जानकारी फैलाने के कारण, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 विवाद का विषय बन गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और वक्फ संपत्तियों के शासन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से बनाए गए इस विधेयक को इन समूहों द्वारा इतना अधिक विकृत किया गया है कि इसकी मूल पहचान ही बदल गयी है। ये निहित स्वार्थ से भरे समूह समुदाय के कल्याण की तुलना में अपने स्वयं के विशेषाधिकारों की रक्षा करने को लेकर अधिक चिंतित हैं।

संशोधन के पीछे का सच

इस विधेयक का विरोध मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो लंबे समय से वक्फ संस्थानों में पारदर्शिता की कमी से लाभान्वित हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से, कुछ समूहों ने वक्फ संपत्तियों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण बनाए रखा है और उनकी पहचान सर्वविदित है। उनका विरोध धार्मिक अधिकारों से जुड़ी वास्तविक चिंताओं से नहीं, बल्कि वर्षों से कुप्रबंधित अकूत संपत्तियों और वित्तीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित है। यदि उनके इरादे वास्तव में समुदाय के कल्याण से जुड़े थे, तो क्या वे बता सकते हैं कि वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय में साल दर साल लगातार गिरावट क्यों आ रही है?

इसमें से सबसे बड़ी विकृतियों में से एक का दावा है कि यह विधेयक सरकार को वैध वक्फ संपत्तियों को जब्त करने में सक्षम बनाता है। वास्तव में, संशोधन केवल जिला कलेक्टर को गलत तरीके से वर्गीकृत संपत्तियों की समीक्षा करने का अधिकार देता है, खासकर ऐसे मामलों में जहां सरकारी या निजी भूमि को गलत तरीके से वक्फ की संपत्ति का नाम दिया गया है। यह उपाय सही स्वामित्व सुनिश्चित करता है और धोखाधड़ी के दावों से बचाता है, जिससे समुदाय और व्यापक सार्वजनिक हित दोनों को लाभ होगा। एक और व्यापक रूप से फैलाया गया मिथक यह है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण को समाप्त कर देता है। इसके विपरीत, यह जिला कलेक्टर को जिम्मेदारी सौंपकर प्रक्रिया को मजबूत करता है, जो स्थापित राजस्व प्रक्रियाओं का उपयोग करके सर्वेक्षण पूरा करेंगे, जिससे निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा अशुद्धियों और संभावित हेरफेर को समाप्त किया जा सकेगा।

हर्ष रंजन

विरोधियों के पाखंड को उजागर करना

इस विधेयक के सबसे मुखर आलोचक वे हैं, जो लंबे समय से वक्फ संपत्तियों के प्रमुख लाभार्थी रहे हैं। उनका विरोध इन संपत्तियों पर बने अपने वित्तीय साम्राज्यों की रक्षा करने से जुड़ा एक सुनियोजित कदम है। इन संगठनों ने ऐतिहासिक रूप से वक्फ संसाधनों पर एकाधिकार बनाए रखा है तथा वे समुदाय के वंचित वर्गों के लिए निर्धारित धनराशि का अपने स्वयं के एजेंडों के लिए उपयोग करते रहे हैं।

पाखंड बहुत बड़ा है! वे मुस्लिम समुदाय के हितों की वकालत करने का दावा करते हैं, जबकि उन्होंने दशकों से व्यक्तिगत लाभ के लिए वक्फ बोर्डों में हेरफेर किया है। भारत में कई वक्फ बोर्ड इन समूहों से जुड़े व्यक्तियों द्वारा संचालित हैं, जो राजनीतिक और वित्तीय लाभ के लिए इन निधियों का गलत इस्तेमाल करते रहे हैं। इस अनियंत्रित गलत इस्तेमाल को संशोधन समाप्त करना चाहता है, जिससे वे सुधार के सबसे मुखर विरोधी बन गये हैं।

वक्फ को सच्चे लाभार्थियों के लिए मजबूत करना

चुनिंदा समूहों के एकाधिकार को तोड़ने के अलावा, यह विधेयक सुन्नी, शिया, बोहरा, आगाखानी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों सहित विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करके समावेशी भावना को बढ़ाता है, जिससे वक्फ संपत्तियों का निष्पक्ष और लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित होगा। इसके अलावा, वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम विशेषज्ञों को शामिल करने से मुस्लिम नियंत्रण को खतरा नहीं है, बल्कि इससे जवाबदेही बढ़ती है और कुप्रबंधन को रोकने में बाहरी निगरानी की सुविधा प्राप्त होती है।

इस विधेयक में वित्तीय ऑडिट और पारदर्शी लेखा पद्धतियों को भी शामिल किया गया है, ताकि वक्फ कोष का दुरुपयोग रोका जा सके। समय-समय पर रिपोर्टिंग की आवश्यकताएँ और वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील करने की सुविधा कानूनी निगरानी को और मजबूत करेगी, जिससे वक्फ संपत्तियों द्वारा अपने इच्छित उद्देश्य पूरा करना, जरूरतमंदों को लाभ पहुँचाना और भारत की समृद्ध समन्वयकारी विरासत को संरक्षित करना सुनिश्चित होगा।

सुधार की आवश्यकता

'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' प्रावधान को हटाने की सरकार की पेशकश वक्फ संपत्ति के दावों में अस्पष्टता को समाप्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रावधान का दुरुपयोग बिना औपचारिक वक्फ समर्पण के भूमि पर अवैध रूप से दावा करने के लिए किया गया है, जिससे अंतहीन कानूनी विवाद और भूमि अतिक्रमण हुए हैं। पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, संशोधन निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की भूमि को गलत दावों से बचाता है, यह सुनिश्चित करता है कि केवल कानूनी रूप से घोषित वक्फ संपत्तियों को ही मान्यता मिले।

आगे का रास्ता

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। इसके प्रावधान; वैध वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने, शासन में सुधार करने और इन संसाधनों से लंबे समय से लाभ उठाने वाले निहित स्वार्थी तत्वों को खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए यह जरूरी है कि वे गलत सूचनाओं को समझें और पहचानें कि इस विधेयक का विरोध करने वाले लोग अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, न कि व्यापक हित के लिए। इस सुधार का समर्थन करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग उनके वास्तविक उद्देश्य - वंचितों का उत्थान और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का संरक्षण - के लिए किया जाए।

अरविंद केजरीवाल व मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से नशे की समस्या पर अंतिम हमला, जन-जागरूकता अभियान की शुरूआत

मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ जंग के लिए हजारों युवाओं को दिलाई शपथ, नशा पीड़ितों की चिताओं पर तस्करों को मुनाफा कमाने की इजाजत नहीं देंगे: भगवंत मान का संकल्प

संवाददाता
लुधियाना

नशों की समस्या पर अंतिम हमला बोलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हजारों युवाओं को शपथ दिलाने के बाद इस खतरे के खिलाफ जन-जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाई। नशे की समस्या के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मार्च पास्ट के लिए आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ह्यह नशे के खिलाफ निर्णायक जंग है और हम पूरे राज्य से इस अभिशाप को खत्म करने का संकल्प लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत हो चुका और अब राज्य सरकार चुपचाप नहीं बैठेगी और नशा पीड़ितों की लाशों और चिताओं पर तस्करों को फलते-फूलते नहीं देखेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही नशों की सप्लाई लाइन तोड़ दी है और इस घृणित अपराध में शामिल बड़े मगरमच्छों को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों द्वारा गैर-कानूनी तरीकों से बनाई गई संपत्ति को प्रांत सरकार ने पहली बार ढहाया या जब्त किया है ताकि यह दूसरों को इस काम में आने से रोके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की खराब कार्यप्रणाली के कारण राज्य में नशे की समस्या बहुत गंभीर हो गई है और यह अब हमारी नसों में घुस चुकी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से प्रेरणा मिली है, जिन्होंने दिल्ली में कई बुराइयों को खत्म करने के साथ-साथ कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के निरंतर नेतृत्व में पंजाब जल्द ही नशों के खतरे से मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ जंग को जन आंदोलन में बदला जाएगा क्योंकि यह सिर्फ पुलिस की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि अब लोग इस अभियान के लिए आगे आ रहे हैं और कई गांवों की पंचायतें नशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने इस जंग में लोगों का सहयोग लेने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 97791-00200 जारी किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने क्षेत्र में अवैध गतिविधियां चला रहे नशा तस्करों के बारे में कोई भी जानकारी इस व्हाट्सएप नंबर पर देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि फोन करने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशों के खिलाफ इस जंग में लोगों का पूरा समर्थन और सहयोग बहुत जरूरी है, जिसके कारण लोगों को इस कदम का बड़े पैमाने पर समर्थन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस ने अनगिनत बलिदान देकर देश की सेवा की है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने मुख्य कर्तव्य को निभाने के अलावा पंजाब पुलिस ने हमेशा देश और लोगों के हितों की रक्षा की है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब पंजाब पुलिस राज्य से नशे के खतरे को खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की जरूरत है कि आम आदमी नशों के खिलाफ जंग में सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, जब हर कोई नशे की बुराई के खिलाफ आगे आए और पैसा कमाने के लिए राज्य की पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे मुट्ठी भर तस्करों का नामो-निशान मिटा दे। भगवंत सिंह मान ने हर पंजाब वासी से नशों के खिलाफ जंग में सिपाही बनने की अपील की ताकि पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाया जा सके।

लुधियाना पश्चिम के लिए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त संशोधन का संशोधित शेड्यूल जारी: सिबिन सी

संवाददाता
चंडीगढ़

भारतीय चुनाव आयोग ने 64-लुधियाना पश्चिम में उपचुनाव के लिए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त संशोधन का शेड्यूल जारी किया है।

जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि मतदाता सूची का विशेष संशोधन, जिसकी अहर्ता तिथि 1-4-2025 होगी, निम्नलिखित शेड्यूल के अनुसार किया जाएगाः

1. मतदान केंद्रों का तार्किक पुनर्गठन - 4-4-2025 तक (शुक्रवार)
2. इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन- 9-4-2025 को (बुधवार)
3. दावों और आपत्तियों को दाखिल करने की अवधि - 9-4-2025 (बुधवार) से 24-4-2025 (गुरुवार) तक
4. दावों और आपत्तियों का निपटारा - 2-5-2025 तक (शुक्रवार)
5. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन - 5-5-2025 को (सोमवार)

सिबिन सी ने बताया कि लुधियाना पश्चिम के लिए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त संशोधन संबंधी राज्य की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को एक पत्र जारी किया जा चुका है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आबकारी और कराधान निरीक्षकों एवं क्लर्कों को नियुक्ति पत्र सौंपे

संवाददाता
चंडीगढ़

प्रदेश की राजस्व प्राप्तियों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आबकारी और कराधान विभाग को और सशक्त करते हुए पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां विभाग के 2 आबकारी और कराधान निरीक्षकों एवं 2 क्लर्कों को नियुक्ति पत्र सौंपे।

नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने लोक सेवा में ईमानदारी, समर्पण और प्रतिबद्धता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सरकार की राजस्व प्राप्ति प्रणाली को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाए रखने में आबकारी और कराधान विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए विश्वास जताया कि नवनियुक्त अधिकारी अपनी योग्यता के बल पर इसमें सार्थक योगदान देंगे।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आबकारी और कराधान विभाग पंजाब सरकार की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य आधार है। उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां विभाग को सक्षम और मेहनती कर्मचारियों की तैनाती के माध्यम से सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दशार्ती हैं, जो प्रभावी राजस्व संग्रह और प्रबंधन में सहायक होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में रोजगार सृजन और कुशल वित्तीय प्रबंधन के प्रति पंजाब सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह भर्ती अभियान न केवल आबकारी और कराधान विभाग को सशक्त करता है, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की पंजाब सरकार की व्यापक नीति का भी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और सशक्तिकरण पर जोर देकर पंजाब सरकार प्रदेशभर में रोजगार के अवसरों और सतत विकास को प्रोत्साहित कर रही है।

युद्ध नशों विरूद्ध: 33वें दिन पंजाब पुलिस ने 59 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

चंडीगढ़। प्रदेश में नशों के समग्र खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निदेर्शों पर चलाई जा रही मुहिम ह्ययुद्ध नशों विरुद्धह्न को 33वें दिन जारी रखते हुए पंजाब पुलिस ने बुधवार को 59 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1.6 किलो हेरोइन और 5.53 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की। इसके साथ ही, महज 33 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 4765 हो गई है। यह ऑपरेशन डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निदेर्शों पर प्रदेश के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कहा है। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया है। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए स्पेशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 91 गजटिड अधिकारियों की निगरानी में 1400 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की गिनती वाली 200 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 497 जगहों पर छापेमारी की।

बाबा साहेब की मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीओ लिखा

संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब राज्य में बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर की मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन स. जसवीर सिंह गढ़ी ने राज्य के पुलिस प्रमुख को डी.ओ. पत्र लिखा है।

स. गढ़ी ने लिखा कि फिल्लौर तहसील के गांव नंगल में भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर देश विरोधी नारे लिखे गए थे। जिसकी जिम्मेदारी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा वीडियो जारी करके ली गई है। इसके मद्देनजर गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ एस.सी/एस.टी एक्ट 1989 के अधीन और देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए और गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा के उसे भारत लाया जाए और उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए मिसाली सजा दी जाए।

इसके साथ ही उन्होंने राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थित बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अंबेडकर जी की मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के लिए भी लिखा ताकि भविष्य में कोई भी असामाजिक तत्व इस तरह की घटना को अंजाम न दे सकें। उन्होंने लिखा कि पंजाब में यदि ऐसी घटनाएं होती रहीं तो पंजाब में आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचने का खतरा है।

10,000 रुपए रिश्वत लेते हुये पीएसपीसीएल लाइनमैन विजिलेंस ब्यूरो द्वारा काबू

संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आज पटियाला में पी.एस.पी.सी.एल. के उत्तरी डिवीजन में तैनात पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) के लाइनमैन और गांव झिल, जिला पटियाला के निवासी जसवीर सिंह को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त पी.एस.पी.सी.एल. कर्मचारी को पटियाला के एक निवासी द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि उक्त मुजजिम जसवीर सिंह द्वारा शिकायतकर्ता के घर में नया घरेलू बिजली मीटर लगाने के बदले रिश्वत की मांग करने के उपरांत शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो के पास पहुंच की। प्रवक्ता ने बताया कि उसकी शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर उक्त आरोपी को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ लिया। विजिलेंस ब्यूरो के कर्मचारियों ने उसके कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद कर ली। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की संबंधित धाराओं के तहत विजिलेंस ब्यूरो के थाना पटियाला रेंज में मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अन्य व्यक्तियों की भूमिका के बारे में जांच जारी है।

संक्षिप्त-समाचार

बिक्रम मजीठिया की सुरक्षा वापस नहीं ली गई, सिर्फ घटाई गई है: पंजाब पुलिस

चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा पूरी तरह से वापस लेने संबंधी रिपोर्टों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि खतरे के पुनर्मूल्यांकन के मद्देनजर उनके सुरक्षा कवच को सिर्फ घटाया गया है, वापस नहीं लिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा समीक्षा समिति की नवीनतम सिफारिशों के बाद यह समायोजन/रद्दो-बदल किया गया था। प्रवक्ता ने कहा, ₹किसी भी प्रमुख व्यक्ति की सुरक्षा की समय-समय पर संभावित खतरे के मूल्यांकन के आधार पर समीक्षा की जाती है। इस आधार पर, सुरक्षा कवच को बढ़ाया या घटाया जाता है,₹ प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बिक्रम मजीठिया के पास अभी भी पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध है, जिसमें एस्कॉर्ट वाहन और पर्याप्त संख्या में बंदूकधारी शामिल है, जो प्रोटोकॉल के अनुसार उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। इस दौरान, अधिकारियों ने दोहराया कि सुरक्षा के लिहाज से ऐसे फैसले आम बात हैं और यह महज संभावित खतरों की रिपोर्टों के आधार पर लिए जाते हैं।

1,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी और उसके सहायक विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार

चंडीगढ़। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ह्यअसहनीयह्न मुहिम को जारी रखते हुए, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एक राजस्व पटवारी और उसके सहायक को 1,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान श्री मुक्तसर साहिब जिले के क्षेत्र वड़िंगखेड़ा के पटवारी कुलविंदर सिंह और उसके सहायक अशोक कुमार के रूप में हुई है। आज यहां यह जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त दोनों मुलजिमों के खिलाफ गांव वड़िंगखेड़ा के एक निवासी द्वारा मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर दर्ज कराई गई शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था। प्रवक्ता ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उक्त पटवारी ने उसकी जमीन की निशानदेही करने के लिए अपने उक्त साथी (अशोक) के माध्यम से 1,500 रुपये रिश्वत की मांग की थी, लेकिन सौदा 1,000 रुपये में तय हो गया। प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि पटवारी द्वारा 5 फरवरी, 2025 को जब जमीन की हदबंदी रिपोर्ट तैयार की गई थी, तब इस संबंध में 2024-25 के सरकारी रजिस्टर या रोजाना डायरी में कोई एंट्री नहीं की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत देने का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया था, जिसमें अशोक कुमार पैसे स्वीकार करते हुए साफ दिखाई दे रहा था। प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस संबंध में दोनों मुलजिमों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 और 7-ए के तहत विजिलेंस ब्यूरो रेंज पुलिस थाना, बठिंडा में केस दर्ज किया गया है। दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

पंजाब पुलिस द्वारा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए क्यूआर कोड प्रमाणिकता की शुरूआत

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निदेर्शों के अनुसार दस्तावेजों संबंधी धोखाधड़ी को रोकने और सुरक्षा में बढ़ोतरी के दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब पुलिस ने पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) के लिए क्यूआर कोड आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य पीसीसी जो अक्सर रोजगार, वीजा और अन्य आधिकारिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक होता है, की प्रमाणिकता की पुष्टि करने के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका प्रदान करना है, इस संबंध में जानकारी देते हुए स्पेशल डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (विशेष डीजीपी) कम्यूनिटी अफेयर्स डिवीजन ने बताया कि इस नई प्रणाली के तहत जारी किए गए हर पीसीसी पर एक विशिष्ट क्यूआर कोड होगा। उन्होंने बताया कि स्कैन करने पर यह क्यूआर कोड उपयोगकताओं को पंजाब पुलिस के आधिकारिक सर्वरों पर उपलब्ध सर्टिफिकेट की सुरक्षित ऑनलाइन कॉपी तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे तुरंत और सही प्रमाणिकता सुनिश्चित की जा सकेगी। पुलिस ने उपयोगकताओं को यह भी सलाह दी है कि वे क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद यह पुष्टि जरूर करें कि पीसीसी को डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ही कनेक्ट हुई है।

राज्य सूचना कमिश्नर हरप्रीत संधू ने यू.टी. के मुख्य सचिव को अपनी चित्र कला की पेश

चंडीगढ़। पंजाब राज्य सूचना कमिश्नर स. हरप्रीत संधू ने आज यू.टी. सचिवालय में मुख्य सचिव यू.टी. चंडीगढ़ श्री राजीव वर्मा को अपनी कलाकृति पेश की। स. हरप्रीत संधू द्वारा तैयार की गई इस चित्र कला ह्यमोर की शान - भारत की शानह्न ने भारत की अमीर सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक शान को विलक्षण ढंग से पेश किया है। यह कलाकृति भारत के राष्ट्रीय पक्षी की महत्ता पर जोर देने और मानव और प्रकृति के बीच आंतरिक बंधन को और मजबूत करने के लिए एक रचनात्मक प्रयास के रूप में काम करती है। इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभिन्न राज्यों-केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को उत्साहित करना है, जो कि भारत की विभिन्न कलाओं को जोड़ने वाली प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने की समुचित जिम्मेदारी को दशार्ता है। इस मौके पर श्री राजीव वर्मा ने हरप्रीत संधू के कलात्मक योगदान को मान्यता दी और इस काम को भारत के पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत का दृश्य प्रतिनिधित्व बताया। उन्होंने पर्यावरण के प्रति चेतना और राष्ट्रीय धरोहरों की कद्र करने की भावना पैदा करने के लिए ऐसी पहलकदमियों की सार्थकता पर जोर दिया। इस मौके पर पंजाब के राज्य सूचना कमिश्नर स. संदीप एस धालीवाल और श्रीमती पूजा गुप्ता भी मौजूद थे।

मीटिंग में किसानों की भलाई के लिए विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई

मोहिंद्र भगत द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों में बागवानी क्षेत्र का अध्ययन करने के निर्देश

संवाददाता
चंडीगढ़

- पंचायती जमीनों पर फलदार वृक्ष लगाने पर भी किया गया विचार-विमर्श
- शानदार कारगुजारी के लिए बागवानी विभाग के अधिकारियों का किया सम्मान

पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंद्र भगत ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों में बागवानी क्षेत्र का अध्ययन करने के निर्देश दिए ताकि पंजाब में बागवानी को और बेहतर तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर से बेहतर अभ्यास अपनाए जा सकें। वे चंडीगढ़ में बागवानी विभाग द्वारा किसानों की भलाई के लिए चलाई जा रही विभिन्न भलाई योजनाओं का जायजा लेने के लिए की गई समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे।

मीटिंग के दौरान बागवानी विभाग के सचिव मुहम्मद तैय्यब और निदेशक शैलेंद्र कौर ने मंत्री को विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को दी जा रही सब्सिडियों और प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी दी। श्री भगत ने इन पहलों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि इनके दायरे को और बढ़ाया जा सके।

मंत्री ने पंचायती जमीनों पर फलदार वृक्ष लगाने पर भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने बागवानी को और प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर दिया ताकि हरियाली बढ़े और किसानों की अतिरिक्त आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे प्रयास केवल किसानों को आर्थिक रूप से लाभ नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि पर्यावरण स्थिरता में भी योगदान देंगे। मीटिंग में, अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण विकास संदीप सिंह ने इन पहलों के लिए पंचायती जमीनों की उपलब्धता और उपयोग के बारे में विवरण साझा किए। मीटिंग में डिप्टी डायरेक्टर हरमेल सिंह भी मौजूद रहे।

अधिकारियों द्वारा उनके काम के प्रति समर्पण को मान्यता देते हुए श्री भगत ने बागवानी योजनाओं को लागू करने में शानदार काम करने के लिए विभाग के कई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इन सम्मानित किए जाने वालों में एच.डी.ओ. बलविंदरजीत कौर, ए.सी.एफ.ए. गुरप्रीत कौर, वरिष्ठ सहायक सुमीत कपूर और राजिंदर कुमार, स्टेनो नवजीत कुमार, क्लर्क हरप्रीत सिंह, रूपिंदरजीत सिंह और अन्य स्टाफ महादेव गुप्ता तथा तुला राम शामिल थे।

इस मौके पर मंत्री ने विकासशील नीतियों और नई पहलों के माध्यम से पंजाब के बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की वचनबद्धता को भी दोहराया।

इजराइल की सेना बमबारी करके दक्षिणी गाजा में घुसी, 17 की मौत

इजराइल के रक्षामंत्री काट्ज ने कहा-हमास के हमदर्द भी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे

सेना हर हाल में हमास के आतंकवादियों और उसके बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करेगी: कैट्ज

एजेंसी (हि.स.)

गाजा पट्टी

फोटोः हि.स.

इजराइल की सेना (आईडीएफ) रातभर बम बरसाते हुए आज सुबह दक्षिणी गाजा में प्रवेश कर गई। इस बमबारी में कम से कम 17 लोग मारे गए। हमास के कई महत्वपूर्ण ठिकाने पलक झपकते ही मटियामेट हो गए। सेना के दक्षिणी गाजा में घुसने पर इजराइल के रक्षामंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि देश की सेना गाजा पर अपने जमीनी हमले का विस्तार कर रही है। अब गाजा पट्टी में व्यापक क्षेत्र पर कब्जा किया जाएगा। साथ ही आतंकवादी समूह हमास के हमदर्द भी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के अनुसार रक्षामंत्री काट्ज ने आज कहा कि देश की थल और नभ सेना गाजा पर अपने जमीनी हमले का विस्तार कर रही है। जल्द ही गाजा पट्टी के बड़े भू-भाग पर नियंत्रण कर उसे गाजा पट्टी के तथाकथित बफर जोन में शामिल किया जाएगा। बताया गया है कि दक्षिणी गाजा पट्टी में इजराइल ने रातभर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। आईडीएफ ने क्षेत्र में एक और डिवीजन तैनात किया है। फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार, इजराइल की फौज ने राफाह और खान यूनिस में रातभर कहर बरपाया है। बुधवार सुबह इजराइल के सैनिक राफाह में आगे बढ़ते दिखे। आईडीएफ ने सोमवार को पूरे राफाह क्षेत्र और खान यूनिस के बीच की भूमि के एक बड़े क्षेत्र के लिए निकासी की चेतावनी जारी की थी। अब तक इस क्षेत्र में शांति रही है। कैट्ज ने कहा कि सेना हर हाल में हमास के आतंकवादियों और उसके बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करेगी। इस बीच गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि बुधवार भोर खान यूनिस और नुसेरात शरणार्थी शिविर में हुए इजराइली हवाई हमलों में बच्चों सहित कम से कम 17 लोग मारे गए। हमास नियंत्रित गाजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि इजराइल के सैन्य अभियान पुनः शुरू करने के बाद से इस क्षेत्र में 1,042 लोग मारे गए हैं। दरअसल, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को हमास नेताओं के सामने सशर्त गाजा छोड़ने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि हमास अगर बिना खूनखराबे के बंधकों को रिहा कर दे तो उसके लड़ाकों को गाजा को खाली करने से नहीं रोका जाएगा। गाजा पट्टी में छिड़े युद्ध के दौरान मिस्त्र, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिर से संघर्ष विराम कराने और इजराइली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

भारतीय नौसेना ने पश्चिमी हिंद महासागर में 2500 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए

संदिग्ध नाव को नियंत्रण में लेकर चालक दल के सदस्यों से विस्तृत पूछताछ की गई

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

पश्चिमी नौसेना कमान के फ्रंटलाइन फ्रिगेट आईएनएस तरकश ने पश्चिमी हिंद महासागर में एक संदिग्ध नाव पर 2500 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को जब्त किया है। भारतीय नौसेना ने जनवरी से समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए पश्चिमी हिंद महासागर में आईएनएस तरकश तैनात किया है, जो संयुक्त टास्क फोर्स का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है। बहरीन में चलाया जा रहा यह अभियान संयुक्त समुद्री बलों (सीएमएफ) का हिस्सा है। भारतीय फ्रंटलाइन फ्रिगेट बहुराष्ट्रीय बलों के संयुक्त फोकस ऑपरेशन 'एन्जैक टाइगर' में भाग ले रहा है। इसी गश्त के दौरान 31 मार्च को भारतीय नौसेना के समुद्री टोही विमान पी-8आई से क्षेत्र में संचालित संदिग्ध जहाजों के बारे में कई इनपुट मिले। ये जहाज मादक पदार्थों की तस्करी सहित अवैध गतिविधियों में शामिल थे। जवाबी कार्यवाही करने के लिए आईएनएस तरकश ने संदिग्ध जहाजों को रोकने के लिए तत्काल अपना रास्ता बदल दिया। जहाज ने आस-पास के सभी संदिग्ध जहाजों से पूछताछ करने के बाद मुंबई में समुद्री संचालन केंद्र के साथ समन्वित प्रयासों के कारण एक संदिग्ध नाव को रोका।

इसके बाद भारतीय युद्धपोत ने संदिग्ध जहाज की गतिविधियों पर नजर रखने और क्षेत्र में संचालित होने वाले अन्य जहाजों की पहचान करने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया। मरीन कमांडो के साथ एक विशेषज्ञ बोर्डिंग टीम संदिग्ध जहाज पर चढ़ी और गहन तलाशी ली। इस दौरान कई सीलबंद पैकेट मिले। आगे की तलाशी में जहाज पर अलग-अलग कार्गो होल्ड और डिब्बों में 2,500 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ पाए गए, जिसमें 2386 किलोग्राम हशीश और 121 किलोग्राम हेरोइन थी। संदिग्ध नाव को आईएनएस तरकश के नियंत्रण में लेकर चालक दल के सदस्यों से विस्तृत पूछताछ की गई। नौसेना के अनुसार यह जब्ती समुद्र में मादक पदार्थों की तस्करी सहित अवैध गतिविधियों को रोकने और बाधित करने में भारतीय नौसेना की प्रभावशीलता और व्यावसायिकता को रेखांकित करती है। बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में भारतीय नौसेना की भागीदारी का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में अंतरराष्ट्रीय जल में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। यह ऑपरेशन समुद्री अपराध से निपटने और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

वक्फ कानून के जरिये गरीब मुसलमानों का उत्थान चाहती है मोदी सरकार: मौर्य

एजेंसी (हि.स.)

लखनऊ

फोटोः हि.स.

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ कानून के जरिये गरीब मुसलमानों का उत्थान चाहती है। यह बात तुष्टिकरण के नुमाइंदों को हजम नहीं हो रही है। इंडी गठबंधन चाहता है कि गरीब मुसलमान हमेशा के लिए गुरबत की जीवन जियें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लोकसभा में वक़्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर कांग्रेस सपा जैसे दलों द्वारा अब मुस्लिमों को भाजपा का भय दिखा उसे केवल वोट बैंक बना दिया। तू मेरा वोट बैंक है की लड़ाई का दिखावा कर रहे हैं, जो व्यर्थ की नूरा कुश्ती है। बहुसंख्य मुसलमानों सहित देश बिल के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सबका विश्वास के साथ स्वागत कर रहा है। कांग्रेस और सपा जैसे दल मुस्लिमों की भलाई के लिए नहीं, सत्ता की मलाई के लिए फर्जी हमदर्दी दिखाने की नौटंकी कर मुद्दा बनाने का असफल प्रयास कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा किसपा - समाप्तवादी पार्टी! अखिलेश यादव डूबती साइकिल को हवाई जहाज बनाने में जुटे हैं, लेकिन जनता अब जान चुकी है कि ये सिर्फ. परिवारवाद, जातिवाद और अपराधवाद की राजनीति करते हैं। फर्जी पीडीए (परिवार डबलपमेंट एजेंसी) के नाम पर माफियाओं, दंगाइयों और भ्रष्टाचारियों को प्रमोट करने की साजिश ज्यादा दिन नहीं चलेगी। यूपी की जनता ने साइकिल पंचर कर दी है। जनभागीदारी से ही संभव है 'स्वच्छता' का संकल्प! यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान एक सामाजिक आंदोलन बन चुका है। हर बार की तरह इस बार भी 1 से 15 अप्रैल तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है।

कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत पर शुरू हुई जांच, डीएमएफ राशि का दुरुपयोग और कोयला चोरी के आरोप

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की खदानों में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की कोयला चोरी का मामला सामने आया है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की शिकायत के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए एसईसीएल, कलेक्टर कोरबा और एसपी को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। भाजपा नेता एवं पूर्वमंत्री ननकी राम कंवर की शिकायत पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य शासन को निर्देश दिया है कि कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत के विरुद्ध डीएमएफ राशि का दुरुपयोग और कोयला चोरी के संबंध में जांच की जाए। ननकी राम कंवर द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं कोयला एवं खनिज मंत्री जी. किशन रेड्डी व अंतर सिंह आर्य केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को शिकायत पत्र देते हुए मांग किया गया है कि कोरबा जिला कलेक्टर अजीत बसंत के द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास मद की राशि का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध राशि का व्यय कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

देहरादून-नैनीताल में विकास को मिली रफ्तार, केंद्र से 164.67 करोड़ की मंजूरी

दून में मल्टीलेबल कार पार्किंग, आढ़त बजार निर्माण सहित कई परियोजनाओं के लिए बजट मंजूर

एजेंसी (हि.स.)

देहरादून

फोटोः हि.स.

केन्द्र सरकार ने देहरादून और नैनीताल में विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत 164.67 करोड़ मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड में बड़ी परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताया। केंद्र सरकार की ओर से जिन विकास कार्यों के लिए बजट मंजूर किया गया है। उसमें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के अधीन रामजीवाला (मियांवाला) में तालाब और पार्क निर्माण के लिए 828.27 लाख रुपए, डिफेंस कॉलोनी में गौरा देवी पार्क निर्माण के लिए 672.57 लाख रुपए, तहसील चौक पर मल्टीलेबल कार पार्किंग और ऑफिस स्पेस बिल्डिंग के लिए 13441.85 लाख रुपए, ऋषिकेश में मल्टीलेबल कार पार्किंग के लिए 12560.70 लाख रुपए, कारगी चौक के पास आढ़त बाजार निर्माण के लिए 12150.38 लाख रुपए, रायपुर के पास मालदेवता रोड पर जलस्रोत सौंदर्यीकरण के लिए 404.85 लाख रुपए , गढ़ी कैंट में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 1215.36 लाख रुपए शामिल है। इसी तरह जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल के अधीन शेर का डांडा में ड्रैनेज और सड़क निर्माण के लिए 1241.59 लाख रुपए और नैनीताल शहर के अंदर सड़क और ड्रैनेज कार्य के लिए 621.10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

संक्षिप्त-समाचार

भाजपा मुख्य अभियुक्तों को बचाने का कार्य कर रही है : दीपक बैज

रायपुर। महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। सीबीआई की छापामार कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने बयान में कहा है कि सीबीआई छापामारी के बाद 21 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। केंद्रीय एजेंसियों के जरिए यह हमें डराना चाहते हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर का नाम 8वे नंबर पर लेकिन भूपेश बघेल का 6वें नंबर पर है। सरकार ने ऐसा करके मुख्य अभियुक्तों को बचाने के लिए कार्य करने की मंशा स्पष्ट कर चुकी है। दीपक बैज ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार क्यों महादेव सट्टा बंद नहीं कर रही है? मंत्री से लेकर नेता की जेब महादेव सट्टा से भर रहा है। इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद सट्टा का कारोबार फल-फूल रहा है। भाजपा इसे बंद करने के बजाय विपक्ष को डराने धमकाने में लगी है जो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने वाली है। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को आरोपित बनाया है। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें भूपेश बघेल छठवें आरोपित के रूप में नामित हैं। कुल 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें महादेव एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल भी शामिल हैं।

पुलिस ने सात साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार, गए जेल

दुमका। पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें तीन दुमका, तीन देवघर और एक पाकुड़ का रहने वाला है। सातों के पास से पुलिस ने 12 मोबाइल, दो लैपटाप, 12 हजार रुपये और एक एटीएम बरामद किया है। गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार युवकों में दुमका के रसिकपुर निवासी विक्की शर्मा, तेलीपाड़ा का नीरज कापरी, काठीकुंड के आमझारी का अंकित कुमार दास, देवघर के खागा का करण कुमार राणा, प्रेम सागर राणा सूरज कुमार और पाकुड़ के राजीव कुमार शामिल है। सभी ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया और बताया कि जनवरी माह से साइबर ठगी कर रहे हैं। एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बुधवार को बताया कि मुफस्सिल थाना प्रभारी को सूचना मिली कि आदित्य नारायण कॉलेज के पास एक निमार्णाधीन मकान में कुछ युवक लैपटॉप के साथ लोगों को अपने जाल में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। प्रशिक्षु आइपीएस डॉ. सैयद मुस्तफा हाशमी के नेतृत्व में टीम बनाकर दबिश दी गई। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार युवकों ने पुलिस को दिए स्वीकारोक्ति बयान में बताया वे सभी लोग कस्मटर केयर में पहले से पड़े मोबाइल नंबर की जगह अपना नंबर डाल देते थे। इसके बाद जो भी कस्टमर शिकायत करता तो उसके मोबाइल नंबर को एक एपीके फाइल में डालकर शिकायत करने वालों को लिंक भेजा करते थे। लिंक के टच करते ही शिकायत करने वाले का खाता से पैसा उड़ा लेते थे। एसपी ने बताया कि इन साइबर अपराधियों ने हाल के वर्षों में जो भी संपत्ति खरीदी होगी, उसे जब्त किया जाएगा। सभी को रिमांड पर लेकर फिर से पूछताछ की जाएगी। इन लोगों ने अभी तक साइबर ठगी से जो भी संपत्ति अर्जित की है, उसका सत्यापन कराया जा रहा है। सभी को बुधवार को जेल भेज दिया गया।

विकिपीडिया को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को एक न्यूज एजेंसी के बारे में प्रोपेगेंडा टूल करने वाली सूचना संपादित करने वाले हिस्से को हटाने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने यह अंतरिम आदेश दिया। उधर, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल को सुनवाई करने वाला है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि विस्तृत आदेश शाम तक कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर, 2024 को कहा था कि किसी न्यूज एजेंसी के लिए इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती है कि उसे सरकार का प्रोपेगेंडा टूल बताया जाए। 05 सितंबर, 2024 को विकिपीडिया के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर आगे कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं होगा तो हम कड़ाई से निपटेंगे। न्यूज एजेंसी ने आरोप लगाया था कि विकिपीडिया वेबसाइट पर उनके बारे में सूचना दी गई है कि वह सरकार का प्रोपेगेंडा टूल है। इस पर हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को आदेश दिया था कि वो इस सूचना को लिखने वाले यूजर का खुलासा करे लेकिन विकिपीडिया ने यूजर का खुलासा नहीं किया। हाई कोर्ट ने जुलाई 2024 में विकिपीडिया को नोटिस भेजकर कहा था कि आपको न्यूज एजेंसी का विवरण संपादित करने वाले का नाम बताना चाहिए। अगर आप नाम नहीं बताएंगे तो न्यूज एजेंसी की ओर से दाखिल याचिका में उसका पक्ष कैसे जाना जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह तब कहा था जब विकिपीडिया ने कहा कि कोर्ट का नोटिस तामील करने की सूचना संबंधित न्यूज एजेंसी को दी जाएगी लेकिन इसमें यूजर की पहचान की जानकारी नहीं होगी। ऐसा होने पर यूजर्स की गोपनीयता सार्वजनिक नहीं होगी और कोर्ट को संबंधित यूजर्स की पूरी जानकारी भी मिल जाएगी।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी अस्वस्थ, कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उनके स्वास्थ्य की जांच की गई है। उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। मीडिया में उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबरें आने के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से संपर्क किया और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। डॉन अखबार के अनुसार, हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय या पीपीपी की ओर से अपने सह अध्यक्ष के स्वास्थ्य के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सुबह मीडिया आउटलेट्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति जरदारी को नवाबशाह से लाए जाने के बाद कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्टी के एक करीबी सूत्र ने बताया कि उनकी कुछ जांचें की जा रही हैं और उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। प्रेस सूचना विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री शहबाज ने राष्ट्रपति से संपर्क किया और उनका हालचाल पूछा और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस बीच, सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के चिकित्सक डॉ. असीम हुसैन को फोन कर जरदारी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

ट्रंप और मस्क को बड़ा झटका, विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट में डेमोक्रेट समर्थित जज क्रॉफोर्ड विजयी

एजेंसी (हि.स.)

वाशिंगटन

फोटोः हि.स.

संयुक्त राज्य अमेरिका में आज हर जुबान पर जज सुसान क्रॉफोर्ड की जीत की चर्चा है। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी डेमोक्रेटिक समर्थित उम्मीदवार जज सुसान क्रॉफोर्ड के विस्कॉन्सिन राज्य के सुप्रीम कोर्ट की दौड़ जीतने की सुर्खी है। इस दौड़ के लिए हुए चुनाव में वो जीत गई हैं। उन्होंने इसके लिए मतदाताओं का आभार जताया है। मीडिया में इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी अरबपति एलन मस्क के लिए सबसे तगड़ा झटका बताया गया है। सीएनएन न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में तीन महीने से भी कम समय में डेन काउंटी में एक उदार सर्किट कोर्ट जज क्रॉफोर्ड ने रूढ़िवादी उम्मीदवार ब्रैड शिमेल को हरा दिया। वो वौकेशा काउंटी के जज हैं। उन्हें चुनाव अभियान के अंतिम चरण में ट्रंप का खुला समर्थन प्राप्त था। क्रॉफोर्ड की जीत को विस्कॉन्सिन और देशभर में डेमोक्रेट के लिए एक उज्ज्वल भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। मतदाताओं ने राष्ट्रपति के पसंदीदा उम्मीदवार को पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा में हरा दिया। एलन मस्क ने इस जनमत संग्रह में अपनी निजी संपत्ति के लाखों डॉलर फूंक दिए। यह अमेरिकी इतिहास की सबसे महंगी न्यायिक प्रतियोगिता बन गई। मंगलवार रात मैडिसन की विजय रैली में क्रॉफोर्ड ने समर्थकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि विस्कॉन्सिन के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर अभूतपूर्व हमले को विफल कर दिया। विस्कॉन्सिन के लोगों ने साबित कर दिया कि अदालतें बिक्री के लिए नहीं हैं। क्रॉफोर्ड ने मस्क का नाम तो नहीं लिया, लेकिन प्रतियोगिता में उनके बड़े खर्च का संदर्भ दिया।

क्रॉफोर्ड ने एक निजी वकील के रूप में प्लांड पैरेंटहुड का प्रतिनिधित्व किया है। वह गर्भपात के अधिकारों का समर्थन करती हैं। क्रॉफोर्ड 10 साल का कार्यकाल पूरा करेंगी। यूएसए टुडे की खबर के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रगतिशील अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने क्रॉफोर्ड को बधाई दी। ओबामा ने मंगलवार रात एक्स पर लिखा, "जज क्रॉफोर्ड को उनकी जीत पर बधाई। विस्कॉन्सिन के लोगों को भी ऐसी जज को चुनने के लिए बधाई, जो कानून के शासन में विश्वास रखती हैं। हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करती हैं। बर्नी सैंडर्स ने भी क्रॉफोर्ड को बधाई देते हुए कहा कि उनकी जीत ने एलन मस्क को हराया है।

स्कूल में ताला तोड़कर हजारों रुपए मूल्य के समानों की चोरी

अररिया। फारबिसगंज थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोला ढोलबज्जा में बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा रसोईघर समेत अन्य कमरों का ताला तोड़कर हजारों रुपये मूल्य के समानों की चोरी कर ली गई। सुबह स्कूल पहुंचने पर प्रधान शिक्षिका मोनिका भारती ने रसोईघर समेत अन्य कमरों के ताला टूटा हुआ और चार क्विंटल मध्याह्न भोजन का चावल सहित मोटर पंप,सिलेंडर,खाना बनाने और परोसने वाले समान को गायब पाया तो फारबिसगंज थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह को स्कूल में चोरी होने की सूचना दी। जिसके बाद फारबिसगंज थाना से पुलिस अधिकारी अमित कुमार और संजीव कुमार मौके पर पहुंचे और स्कूल में हुए चोरी की मुआयना की। मामले को लेकर स्कूल की प्रधान शिक्षिका मोनिका भारती के द्वारा फारबिसगंज थानाध्यक्ष को एक लिखित आवेदन देकर स्कूल में चोरी होने और अज्ञात चोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है इससे पूर्व भी स्कूल में कई दफा अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना हुई है।

अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 10 भूटानी शरणार्थियों में से तीन को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया

एजेंसी (हि.स.)

काठमांडू

फोटोः हि.स.

अमेरिका द्वारा डिपोर्ट किए गए 10 भूटानी नागरिकों को भूटान सरकार ने अपने यहां रखने से इनकार करते हुए उन सभी को वापस नेपाल भेज दिया है। इनमें से तीन भूटानी शरणार्थियों को नेपाल में अवैध रूप से प्रवेश करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका जाने से पहले ये सभी 10 लोग नेपाल के भूटानी शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे। नेपाल के झापा जिले के एसपी मिलन केसी ने बुधवार को मीडियाकर्मियों को बताया कि अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के बाद अवैध रूप से नेपाल में प्रवेश करने वाले 10 में से तीन भूटानी नागरिकों को मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता लगा है कि अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद भूटान सरकार ने उन्हें अपने यहां रखने से इनकार कर दिया जिसके बाद वो भारत के रास्ते नेपाल में दोबारा आ गए हैं।

अमेरिका की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नेपाल में रह रहे भूटानी शरणार्थियों को ले जाया गया था लेकिन अब उनको अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है। बीते सोमवार को अमेरिका से दिल्ली होते हुए थिंपू भेजे गए 10 नागरिकों को भूटान सरकार ने अपने यहां रखने से इनकार किया है। नेपाल में पुलिस नियंत्रण में लिए गए भूटानी नागरिकों ने बताया कि अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद उन्हें जब सोमवार को थिंपू एयरपोर्ट पर उतारा गया तो वहां की सरकार ने प्रति व्यक्ति 30 हजार रुपये देकर भूटान से विदा कर दिया। नेपाल में गिरफ्तार किए गए भूटानी नागरिकों ने बताया कि चूंकि वो नेपाल के भूटानी शरणार्थी शिविर से अमेरिका गए थे इसलिए भूटान सरकार ने उन्हें दोबारा शरणार्थी शिविर में रहने के लिए भेजा है।

नेपाल-थाईलैंड प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)

काठमांडू

थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा पर गए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेटोंगटार्न शिनावात्रा के बीच बुधवार को बैंकाक में हुई मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। बैंकाक में दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच बैठक में शामिल हुईं नेपाल की विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा देउवा ने कहा कि थाईलैंड के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापना के 65 साल के बाद पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा होना अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे पहले थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने एक सरकारी इमारत में प्रधानमंत्री ओली का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बैठक के बाद संस्कृति और पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। नेपाल की तरफ से विदेश मंत्री डॉ. आरजू ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसी तरह दोनों देशों के गैर-सरकारी और व्यावसायिक संगठनों के बीच छह अलग-अलग समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में एक दूसरे देशों को पर्यटन, शिक्षा, तकनीकी क्षेत्र में सहयोग आदान प्रदान करने पर जोड़ दिया।

जीईएम ने वित्त वर्ष 2024-25 में बनाया रिकॉर्ड, 10 लाख से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

डिजिटल खरीद मंच गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी संगठनों के लिए 10 लाख से अधिक जनशक्ति संसाधनों की भर्ती करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में बताया कि जीईएम की यह उपलब्धि पारदर्शिता, अनुपालन और दक्षता के माध्यम से सार्वजनिक खरीद को बदलने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। जीईएम की इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 'एक्स' पोस्ट पर एक बयान में जीईएम प्लेटफॉर्म की सफलता और इसके माध्यम से रोजगार के अवसरों पर अपनी बात साझा की। उन्होंने इस प्लेटफार्म के जरिए 10 लाख से अधिक कर्मचारियों की भर्ती के आंकड़े को ऐतिहासिक बताया। पीयूष गोयल ने एक्स पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीईएम विशाल रोजगार सृजन में सहायक बन रहा है और श्रमिकों की भर्ती के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। यह प्लेटफॉर्म वित्त वर्ष 2024-25 के तहत 10 लाख से अधिक कर्मचारियों की भर्ती का महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर चुका है, जो इसकी व्यापक स्वीकृति और सरकारी संगठनों में प्रभाव को दर्शाता है।

इस उपलब्धि पर जीईएम के सीईओ अजय भादू ने कहा, जीईएम ने डिजिटल क्षमताओं का दोहन किया है और प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सरकारी खरीदारों द्वारा आवश्यक सभी संभावित सेवाओं की खरीद के लिए वन-स्टॉप-शॉप के रूप में उभरा है। हमारी मैनपावर आउटसोर्सिंग सेवा न केवल सरकारी संगठनों के लिए भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाती है, बल्कि हमारे व्यापक सेवा स्तर समझौते के माध्यम से सख्त श्रम अनुपालन भी सुनिश्चित करती है। जीईएम की मैनपावर आउटसोर्सिंग सरकारी खरीदारों को आउटसोर्स संसाधनों को काम पर रखने के लिए एक सहज समाधान प्रदान करती है। इस प्लेटफॉर्म पर 33 हजार से ज्यादा सेवा प्रदाता खरीदारों को न्यूनतम वेतन और निश्चित पारिश्रमिक सहित विभिन्न मानदंडों के आधार पर मैनपावर को शामिल करने में सक्षम बनाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर सुरक्षाकर्मी, बागवानी कर्मचारी, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सुविधा प्रबंधन पेशेवरों जैसी विभिन्न कुशल और अकुशल भूमिकाओं को पोर्टल के माध्यम से काम पर रखा जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि 2016 में स्थापित जीईएम सरकारी खरीदारों को लागत प्रभावी दरों पर सार्वजनिक खरीद करने के लिए एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2019-20 में इस प्लेटफॉर्म ने एक अलग सेगमेंट के रूप में सेवाओं को शामिल करने के लिए विस्तार किया। इस प्लेटफॉर्म ने शुरूआत में मैनपावर हायरिंग, कैब हायरिंग, सुरक्षा सेवाएं और सफाई और स्वच्छता सेवाएं जैसी बुनियादी सेवाएँ प्रदान कीं। पिछले पांच वर्षों में जीईएम ने अपने पोर्टफोलियो का विस्तार 330 से अधिक सेवाओं तक किया है, जिसमें ड्रोन सेवाएं, एआर/वीआर सेवाएं, क्लाउड सेवाएं और साइबर सुरक्षा सेवाएं जैसी जटिल पेशकश शामिल हैं।

रियल मैड्रिड ने रियल सोसिएदाद को हराकर फाइनल में बनाई जगह

कोपा डेल रे सेमीफाइनल मुकाबले में एंटोनियो रूडिगर बने हीरो

एजेंसी (हि.स.)
मैड्रिड

रियल मैड्रिड ने मंगलवार को रियल सोसिएदाद के खिलाफ रोमांचक 4-4 के ड्रॉ के साथ कोपा डेल रे के फाइनल में जगह बनाई, जिससे उसने कुल 5-4 के स्कोर के साथ सेमीफाइनल जीत लिया। एंटोनियो रूडिगर ने 115वें मिनट में हेडर के जरिए निर्णायक गोल किया, जिससे मैड्रिड अब फाइनल में बार्सिलोना या एटलेटिको मैड्रिड का सामना करेगा।

पहले चरण में 1-0 से पिछड़ रही रियल सोसिएदाद ने एंडर बार्रेनचेया के गोल से बढ़त बनाई, लेकिन एंड्रिक के शानदार चिप शॉट से रियल मैड्रिड ने बराबरी कर ली। डेविड अलाबा के आत्मघाती गोल और मिकेल ओयारजाबल के डिफ्लेक्टेड शॉट से सोसिएदाद को बढ़त मिली, लेकिन मैड्रिड ने जूड बेलिंघम और ऑरेलियन चुआमेनी के गोलों से वापसी की। ओयारजाबल ने स्टॉपेज टाइम में दूसरा गोल कर मुकाबले को अतिरिक्त समय तक खींचा, लेकिन सोसिएदाद पेनल्टी तक मुकाबला नहीं ले जा सकी। अंततः रूडिगर के हेडर ने मैड्रिड को फाइनल में पहुंचा दिया।

आज को एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच दूसरे सेमीफाइनल का मुकाबला होगा

फोटोः हि.स.

मैड्रिड के कोच कार्लो एंसेलोटी ने विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो को शुरूआती लाइनअप में रखा, जबकि काइलियन एम्बाप्पे को आराम दिया और उनकी जगह एंड्रिक को मौका मिला। 18 वर्षीय एंड्रिक, जिन्होंने पहले चरण में एकमात्र गोल किया था, शुरूआती मिनटों में सक्रिय दिखे और एक शानदार ओवरहेड किक से गोल करने के करीब पहुंचे। बेलिंघम ने भी गोल करने की कोशिश की, लेकिन बढ़त रियल सोसिएदाद ने ली। बार्रेनचेया ने पाब्लो मारिन के पास पर बढ़त बनाते हुए गोल किया। हालांकि, मैड्रिड ने जल्द ही बराबरी कर ली। विनीसियस ने बाएं फ्लैंक से बेहतरीन थ्रू बॉल दी, जिस पर एंड्रिक ने शानदार लोब्ड फिनिश करते हुए गोल किया।

सोसिएदाद ने पहले हाफ के अंत में पेनल्टी की मांग की, जब ताकेफुसा कुबो बॉक्स में विनीसियस से टकरा गए, लेकिन रेफरी ने इसे खारिज कर दिया। दूसरे हाफ में एंसेलोटी ने एंड्रिक की जगह एम्बाप्पे को मैदान पर उतारा, लेकिन मौके बनाने में सोसिएदाद अधिक सफल दिखी। गोलकीपर आंद्रिय लूनिन ने मार्टिन जुबिमेंडी का शानदार बचाव किया, लेकिन 72वें मिनट में मारिन के क्रॉस पर अलाबा का आत्मघाती गोल हुआ, जिससे सोसिएदाद को बढ़त मिली। इसके बाद ओयारजाबाल का डिफ्लेक्टेड शॉट लूनिन को छकाते हुए गोल में चला गया, जिससे सोसिएदाद की बढ़त और मजबूत हो गई।

लेकिन इसके बाद मैड्रिड ने जोरदार वापसी की। 82वें मिनट में विनीसियस के पास पर बेलिंघम ने गोल किया और चार मिनट बाद चुआमेनी के हेडर पर गोलकीपर रेमिरो की गलती से स्कोर 4-4 हो गया। 90+3वें मिनट में ओयारजाबाल के हेडर से मुकाबला अतिरिक्त समय तक गया, लेकिन सोसिएदाद अंतिम क्षणों तक बढ़त नहीं बचा सकी। अंततः 115वें मिनट में अरदा गुलर के कॉर्नर पर रूडिगर के बेहतरीन हेडर ने मैड्रिड को फाइनल में पहुंचा दिया। अब बुधवार को एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच दूसरे सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। दोनों टीमें पहले चरण में 4-4 की बराबरी पर हैं।

शार्लेट एडवर्ड्स बनीं इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की नई हेड कोच

एजेंसी (हि.स.)
लंदन

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने मंगलवार को शार्लेट एडवर्ड्स को इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। पूर्व इंग्लैंड कप्तान एडवर्ड्स ने अपने देश के लिए 300 से अधिक मैच खेले हैं और अपने 20 साल के क्रिकेट करियर में दो वर्ल्ड कप और पाँच बार एशेज ट्रॉफी जीती है। 2017 में संन्यास लेने के बाद, एडवर्ड्स ने इंग्लिश घरेलू क्रिकेट और वैश्विक टी20 लीगों में कोचिंग की है। उन्होंने दक्षिणी वाइपर, द हंड्रेड में साउदर्न ब्रेव, विमेंस बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स और विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के साथ सफलता हासिल की है।

फोटोः हि.स.

अपनी नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए एडवर्ड्स ने कहा, इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के नेतृत्व का फिर से हिस्सा बनने पर मैं बेहद रोमांचित हूं। इस टीम को आगे ले जाना और सफलता की ओर बढ़ाना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे लिए फिर से तीन शेरों (इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम का लोगो) को धारण करना दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। इंग्लैंड की कप्तानी करना मेरे जीवन का अहम हिस्सा रहा है और मैं हमेशा इस टीम और इसकी विरासत के प्रति समर्पित रहूंगी। हमारे पास प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का एक बेहतरीन समूह है, और मैं उनके साथ काम करने और उन्हें व्यक्तिगत और टीम स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हूं।

उन्होंने आगे कहा, हमारे सामने दो घरेलू सीरीज का त्वरित चुनौती है, जिसके बाद इस साल के अंत में भारत में आईसीसी महिला विश्व कप खेला जाना है। अगले साल इंग्लैंड में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप भी होगा और इसके बाद 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में महिला क्रिकेट की पहली उपस्थिति होगी। मैं इस टीम के साथ ट्रॉफी जीतने और इसे आगे ले जाने के लिए तैयार हूं।

ईसीबी की डिप्टी सीईओ और इंग्लैंड महिला क्रिकेट की मैनेजिंग डायरेक्टर क्लेयर कॉनर ने कहा, जब हमने इस पद के लिए मानदंड तय किए, तो यह जल्दी स्पष्ट हो गया कि शार्लेट एडवर्ड्स सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हैं। उन्होंने आगे कहा, उनके पास अनुभव, जुनून और विशेषज्ञता है, जो इस टीम को सफलता की ओर ले जा सकती है। बतौर हेड कोच उन्होंने अलग-अलग टीमों के साथ बेहतरीन नतीजे दिए हैं। यह उनके निरंतर प्रयास और उच्च मानकों का प्रमाण है।

वह एक सिद्ध विजेता हैं, जिन्होंने एक खिलाड़ी और अब कोच के रूप में लगातार सफलता हासिल की है। शार्लेट एडवर्ड्स वर्तमान में हैम्पशायर से ईसीबी में शामिल हो रही हैं। इंग्लैंड महिला टीम की हेड कोच के रूप में उनका पहला मैच 21 मई को वेस्टइंडीज के खिलाफ कैंटरबरी में होगा। इंग्लैंड महिला टीम के नए कप्तान की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

भारतीय तीरंदाजी टीम को अप्रैल में होने वाले विश्व कप चरण-1 के लिए नहीं मिला अमेरिकी वीजा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

भारतीय तीरंदाजी टीम ने घोषणा की है कि वह अमेरिकी वीजा प्राप्त करने में असमर्थ है और संभवतः 8 से 13 अप्रैल तक फ्लोरिडा में होने वाले विश्व कप स्टेज-1 प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगी। भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) ने खुलासा किया कि 16 सदस्यीय टीम को अप्रत्याशित सिस्टम मुद्दों के कारण वीजा अपॉइंटमेंट प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एएआई ने इंस्टाग्राम पर कहा, दुर्भाग्य से पिछले 40 दिनों में हमारे अथक प्रयासों और कई फॉलो-अप के बावजूद भारतीय तीरंदाजी टीम को अप्रत्याशित सिस्टम मुद्दों के कारण अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट प्राप्त करने में अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप, हम आगामी विश्व कप प्रतियोगिता से बाहर होने के कगार पर हैं, जिसका हमारी भागीदारी और प्रतिस्पर्धी संभावनाओं पर गंभीर असर पड़ेगा। इस मुद्दे को हल करने और हमारी टीम के लिए संभावित झटके को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप जरूरी है। 2025 विश्व कप में पांच प्रतियोगिताएं शामिल हैं और यह 8 अप्रैल से 19 अक्टूबर तक चलेगा।

भारतीय टीम

रिकर्व पुरुषः धीरज बोम्मदेवरा, तरुणदीप राय, अतनु दास और पार्थ सुशांत सालुंखे।
रिकर्व महिलाः अंकिता भक्त, दीपिका कुमारी, सिमरनजीत कौर और अंशिका कुमारी।
कंपाउंड मैनः अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव, ओजस प्रवीण देवताले और उदय कंबोज।
मिश्रित महिलाएंः मधुरा धमनगांवकर, ज्योति सुरेखा वेन्नम, तानीपर्थी चिकिथा और अदिति स्वामी।

वेस्ट इंडीज 1975 विश्व कप की ऐतिहासिक जीत की 50वीं वर्षगांठ मनाएगा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

वेस्ट इंडीज अपनी ऐतिहासिक 1975 विश्व कप जीत की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, जिसे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन में 21 जून 1975 को हासिल किया गया था। उस समय इसे 'प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप' कहा जाता था। इस टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लाइव लॉयड की शानदार सेंचुरी ने वेस्ट इंडीज को 17 रन से जीत दिलाई थी और लॉयड ने ट्रॉफी उठाई थी। वेस्ट इंडीज के इस ऐतिहासिक सम्मान समारोह का आयोजन बारबाडोस में होगा, हालांकि अभी तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने इस योजना का स्वागत करते हुए कहा, यह एक बेहतरीन विचार है। मैं विस्तार से तो नहीं जानता, लेकिन यह बहुत अच्छा है कि हम अपनी उपलब्धियों को मान्यता दे रहे हैं। होल्डिंग, जो 1975 के विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा नहीं थे, 1979 और 1983 के विश्व कप में वेस्ट इंडीज का हिस्सा रहे। 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को फाइनल में हराया था। होल्डिंग ने आगे कहा, सभी अन्य देश अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं और हमें भी अपनी कहानी लिखनी चाहिए और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए।

1975 की विश्व कप जीत वेस्ट इंडीज क्रिकेट इतिहास के सबसे महान क्षणों में से एक मानी जाती है, जो उनके विश्व क्रिकेट में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के समय पर आई। वेस्ट इंडीज का प्रभुत्व अगले दशक तक बना रहा, लेकिन उसके बाद टीम के प्रदर्शन में गिरावट आई, और तब से वह पूरी तरह से वापस नहीं आ सकी है। सीडब्ल्यूआई के अध्यक्ष डॉ. किशोर शैलो ने हाल ही में मीडिया सम्मेलन में इस आयोजन की योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा, इस साल हम 1975 में हुई अपनी पहली विश्व कप जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम आयोजन के अंतिम चरण में हैं, कुछ चीजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डॉ. शैलो ने स्पोर्ट्समैक्स वेबसाइट को बताया, यह हमारे वार्षिक कैलेंडर का एक प्रमुख हिस्सा होगा।

उत्तर मध्य रेलवे की महिला हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक

प्रयागराज। मार्च के अंतिम सप्ताह में आयोजित अंतर रेलवे प्रतियोगिताओं में उत्तर मध्य रेलवे के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जोन को गौरवान्वित किया। उत्तर मध्य रेलवे की टीमों और खिलाड़ियों को महाप्रबंधक उत्तर उपेंद्र चंद्र जोशी ने शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए आगे बेहतर प्रदर्शन के लिए सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी वे उत्तर मध्य रेलवे और राष्ट्र के लिए इसी तरह उपलब्धियां हासिल करेंगे। वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया कि 22 से 28 मार्च तक एमसीएफ रायबरेली (यूपी) में आयोजित अंतर रेलवे महिला हॉकी चैम्पियनशिप में उत्तर मध्य रेलवे की टीम ने कांस्य पदक जीता। टीम की कोच नीलम व मैनेजर रचना चौरसिया थीं। गुरजीत कौर और निशा वारसी सहित अन्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों से सज्जित उत्तर मध्य रेलवे की महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक मैच में पिछली बार की चैम्पियन साउथ ईस्टर्न रेलवे को 5-3 से हराया।

एलएसजी के गेंदबाज दिग्वेश सिंह पर लगा मैच फीस का 25% जुमार्ना

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

मंगलवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 मैच के दौरान एलएसजी के तेज गेंदबाज दिग्वेश सिंह को आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इसके चलते उन्हें उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुमार्ना भरना होगा और साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है। दिग्वेश ने पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रियांश आर्य को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कराया, आर्या डग-आउट की ओर जा रहे थे, तो दिग्वेश ने उनका पीछा किया और एक काल्पनिक नोटबुक पर लिखना शुरू कर दिया। हालांकि बल्लेबाज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। गौरतलब है कि पिछले साल दिल्ली प्रीमियर लीग में दोनों ने एक ही टीम का प्रतिनिधित्व किया था। दिग्वेश की इस हरकत को आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन माना गया। दिग्वेश ने लेवल 1 अपराध के तहत अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करना स्वीकार किया और मैच रेफरी द्वारा दी गई सजा को स्वीकार कर लिया। आचार संहिता के अनुसार, लेवल 1 के उल्लंघन के मामलों में मैच रेफरी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। आईपीएल के नियमों के अनुसार, यदि किसी खिलाड़ी के चार डिमेरिट पॉइंट जुड़ जाते हैं, तो उन्हें एक मैच के लिए निलंबित किया जा सकता है। हालांकि, दिग्वेश पर अभी सिर्फ एक डिमेरिट पॉइंट लगा है, इसलिए उन्हें किसी निलंबन का सामना नहीं करना पड़ेगा।

दर्पण

अप्रैल के दिनों में घूमना चाहते हैं तो इन जगहों पर बिता सकते हैं समय

अप्रैल के महीने में जब भारत में दस्तक देने का समय आता है तो वसंत की खुशबू धीरे-धीरे छुट्टियों के मूड में बदल जाती है। इस महीने में गर्मी की हल्की-हल्की फुहारें पड़ती हैं, साथ ही शुष्क, खुशनुमा हवा आती है, साथ ही स्कूलों की छुट्टियाँ भी हो जाती हैं और परिवार ठंडी जलवायु की तलाश में छुट्टियाँ मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस महीने में, अधिकांश हिमालयी और ऊपरी उत्तरी गंतव्य, साथ ही पहाड़ियों या तट के पास स्थित दक्षिण भारतीय गंतव्य अपने ठंडे मौसम के लिए मशहूर हो जाते हैं। दार्जिलिंग, मसूरी, मनाली, सोनमर्ग, त्रिवेंद्रम, कुन्नूर आदि जैसे गंतव्य भारत में अप्रैल में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से हैं। अप्रैल में ऐसी ही और जगहों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आगे पढ़ें।

दार्जिलिंग

हिमालय पर्वतमाला में बसा दार्जिलिंग चाय के बागानों, पहाड़ियों और घाटियों का एक खूबसूरत स्वर्ग है। पश्चिम बंगाल राज्य का एक हिस्सा, दार्जिलिंग भारत के सबसे रोमांटिक पहाड़ी इलाकों में से एक है, जो गर्मियों के महीनों में सुखद तापमान और सुंदर, पर्यटन गतिविधियों से भरा हुआ है। अप्रैल का महीना दार्जिलिंग घूमने के लिए सबसे अच्छा होता है, इस दौरान तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। बारिश और ओले पड़ने की संभावना है, इसलिए कुछ हल्के ऊनी कपड़े साथ ले जाने की सलाह दी जाती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे से शुरूआत करें, जो 78 किमी लंबी टॉय ट्रेन है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा का नजारा लेने के लिए टाइगर हिल जाएं, हिम तेंदुआ, लाल पांडा और हिमालयी भेड़िया जैसे कुछ दुर्लभ हिमालयी जानवरों को देखने के लिए पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर जाएं। आप मिरिक में इसके बागों से ताजे रसदार संतरे, सुमांडू झील और देवी स्टेन और बोकार मठ जैसे मंदिरों के लिए भी जा सकते हैं। रंगीत घाटी में केबल कार की सवारी का आनंद लें, जहां आपके नीचे दार्जिलिंग शहर, बहती नदियां, ताजे छंटे हुए चाय के बागान और हरी घास के मैदानों से भरी घाटियां हैं।

मनाली

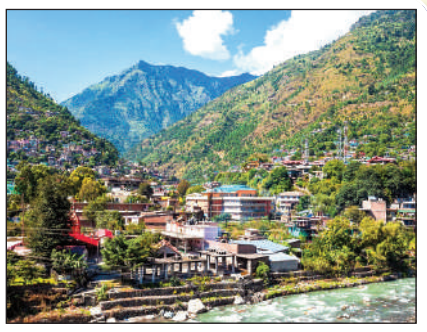

मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित है, खास तौर पर कुल्लू जिले में जिसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। यह शहर जो हाल ही में 'ये जवानी है दीवानी' का पर्याय बन गया है, हमेशा से ही उन यात्रियों के रडार पर रहा है जो हिल स्टेशन पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं और साथ ही कुछ रोमांच भी चाहते हैं। इसमें एक अनोखी पुरानी दुनिया का आकर्षण है और यह हिमाचल प्रदेश के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है; खासकर अप्रैल में, जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। सुहावने दिन और ठंडी रातें, आलीशान रिसॉर्ट और होटल, जीतने के लिए बहुत सारे पहाड़। गर्मियों के लिए एकदम सही। तिब्बती मठों जैसे गढ़न थेकचोकिंग गोम्पा, हिमालयन निंगमापा गोम्पा (इसमें शाक्यमुनि यानी भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है) और पांडेन नगरी गोम्पा की यात्रा से शुरूआत करें। मनु ऋषि मंदिर, वशिष्ठ मंदिर और हडिम्बा देवी मंदिर भी देखें। मनाली के सेब के बागों को देखें, पुरानी दुनिया के आकर्षण के लिए सड़कों पर टहलें, गर्म सल्फर झरने में स्नान करने के लिए ब्यास के पार वशिष्ठ के छोटे से गाँव में जाएँ। रोमांच के दीवानों के लिए, हिमाचल प्रदेश पर्यटन नियमित रूप से रॉक क्लाइम्बिंग, स्कीइंग और पर्वतारोहण के पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

मसूरी

मसूरी उत्तराखंड के नवगठित राज्य में एक हिल स्टेशन है, जो राज्य की राजधानी देहरादून से केवल 35 किमी दूर है। 6,170 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस हिल स्टेशन में कुछ अद्भुत वनस्पतियां और जीव-जंतु हैं। मसूरी में 1850 में स्थापित एक बीयर ब्रूअरी भी है। अप्रैल में मसूरी में पर्यटन का मौसम शुरू होता है, जिसमें सर्दियां पिघलती हैं और गर्मियों में मौसम खुशनुमा हो जाता है। तापमान 10-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह शहर मसूरी झील के आसपास बसा हुआ है और यहाँ आना अनिवार्य है। केम्प्टी फॉल्स से लेकर झड़ीपानी फॉल्स और भट्टा फॉल्स तक के झरने भी देखने लायक हैं। आप नाव किराए पर लेकर लेक मिस्ट में सवारी कर सकते हैं या लाल टिब्बा में एक शांत, शांतिपूर्ण सूर्योदय का आनंद ले सकते हैं। धनौल्टी का इलाका भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित पर्यटक आकर्षण है, मुख्य रूप से रोडोडेंड्रोन फूलों, देवदार और ओक के पेड़ों के खिलने वाले खेतों के लिए। आप हैप्पी वैली, गन हिल भी देख सकते हैं और शहर के बाजार में घूम सकते हैं, जिसे मॉल रोड भी कहा जाता है। इस जगह में औपनिवेशिक आकर्षण है और यहाँ अंग्रेजी बेंच, लैंप पोस्ट और पक्की सड़कें हैं।

डलहौजी

डलहौजी हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के पास स्थित एक ग्रीष्मकालीन हिल स्टेशन है। इस जगह की शांति और शांतता थके हुए लोगों को तनावमुक्त करने और तरोताजा करने के लिए जानी जाती है। यात्री और पर्यटक आमतौर पर शांति, कुछ ठंडी पहाड़ी विलासिता और औपनिवेशिक युग के आकर्षण में डूबने के लिए यहाँ आते हैं। यह एक खूबसूरत हनीमून डेस्टिनेशन भी है। अप्रैल में डलहौजी में वसंत का अंत और गर्मियों की शुरूआत होती है, यहाँ तक कि गर्मियों के चरम पर भी तापमान कभी भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। सुंदर दृश्यों के लिए खज्जर शहर जाएँ, लंबी सैर करें और पिकनिक का आनंद लें। डलहौजी में ही, सेंट फ्रांसिस और सेंट जॉन चर्च जैसी कई औपनिवेशिक इमारतें हैं जो शहर में पुरानी दुनिया के आकर्षण को भर देती हैं। दोनकुंड चोटी तक ट्रेक करें और सुभाष बावली में कुछ शांत समय और मनोरम दृश्यों का आनंद लेते हुए फूलानी देवी मंदिर में पूजा करें। लंबी प्रकृति की सैर, वन्यजीवों के दर्शन और स्फूर्तिदायक अनुभव के लिए कालाटोप वन्यजीव अभ्यारण्य देखें। पंचपुला एक और ट्रैकिंग और पिकनिक स्थल है, जबकि चमेरा झील रोमांच और फोटोग्राफी के लिए जानी जाती है।

पेलिंग

सिक्किम में मनमोहक परिदृश्य का एक टुकड़ा, पेलिंग एक आकर्षक शहर है जो हाल के वर्षों में एक प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल बन गया है। हरे-भरे जंगलों, झीलों, झरनों और कुछ मनमोहक वन्य जीवन से भरा हुआ। जबकि सिक्किम सर्दियों में जम जाता है और मानसून में बहुत गीला रहता है, गर्मियों में 7 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ पर्यटकों के लिए स्वागत योग्य हो जाता है। शुष्क, धूप वाले दिन होते हैं और अप्रैल बस उन दिनों का प्रवेश द्वार बन जाता है। सिक्किम में जब भी जाएं, तो कंचनजंगा की विशाल चोटी को देखने जरूर जाएं। सांगाचोलिंग मठ, पेमायांगत्से मठ पर जाएं और हर एक मठ को उसके अपने गुणों के लिए देखें। यहां ट्रैकिंग भी अच्छी है, खास तौर पर खेचोपलरी झील के रास्ते और भाले धुंगा पर। आपको सेवारो रॉक गार्डन, सिंगशोर ब्रिज, रिम्बी झरना और कंचनजंगा फॉल भी जरूर देखना चाहिए। सिक्किम कुछ अच्छे तिब्बती और चीनी व्यंजनों के लिए जाना जाता है और नूडल स्टू और मोमोज खाने के लिए सबसे अच्छी जगहें मेल्टिंग पॉइंट, द रबडेंटसे और बिग बाउल हैं। यहां खरीदारी करना अच्छा है, और इसमें कालीन, कंबल, शॉल, नक्काशीदार टेबल और पारंपरिक तिब्बती पेंटिंग शामिल हैं।

तिरुवनंतपुरम

त्रिवेंद्रम केरल का राजधानी शहर है, और काफी व्यस्त भी। फिर भी, केरल के बेहतरीन स्थानों की यात्रा करते समय यह एक सुंदर पर्यटक स्थल और छुट्टी मनाने का स्थान है। तिरुवनंतपुरम के नाम से भी जाना जाने वाला यह शहर एक विशिष्ट आकर्षण रखता है, जो औपनिवेशिक वास्तुकला की छाप रखता है। यहाँ त्रावणकोर राजपरिवार के अवशेष भी हैं। अप्रैल में यहाँ का औसत तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रहता है और कभी-कभार प्री-मानसून बारिश की उम्मीद की जा सकती है। त्रिवेंद्रम में आपको नेय्यर बांध और वन्यजीव अभयारण्य में इसके अद्भुत मगरमच्छ फार्म, हिरण पार्क, शेर सफारी और नेय्यर नदी में नौका विहार के लिए जाना चाहिए। यहां पेप्पारा बांध और वन्यजीव अभयारण्य भी है। यहां का एक और आश्चर्य अंजेंगो या अंचुथेंगु किला है, जो अपनी औपनिवेशिक शक्ति से परिपूर्ण है। जूलॉजिकल गार्डन, नेपियर संग्रहालय और त्रावणकोर राजघरानों के कुथिरा मलिका पैलेस का अन्वेषण करें। त्रिवेंद्रम से 16 किमी दूर कोवलम का समुद्र तटीय शहर है, जो अपने प्राचीन तटों के लिए प्रसिद्ध है। आपको वहां बीच रिट्रीट की योजना जरूर बनानी चाहिए। यहां के रोमांच में स्काईडाइविंग, स्कूबा डाइविंग और पर्वतारोहण शामिल हैं।

गृह सचिव ने वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की समीक्षा बैठक की

'सभी मौजूदा वर्षा जल संचयन प्रणालियों को जियो-टैग किया जाएगा'

अभियान में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की योजनाओं पर भी चर्चा की गई

संवाददाता
चंडीगढ़

भारत सरकार ने 22 मार्च, 2025 को 'जल संचय, जन भागीदारी- जन जागरूकता की ओर' थीम के साथ 'जल शक्ति अभियानः कैच द रेन 2025' अभियान शुरू किया, ताकि वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा दिया जा सके। इस पहल के बाद, यूटी चंडीगढ़ प्रशासन के गृह सचिव-सह-जल संसाधन सचिव मंदीप सिंह बराड़ द्वारा प्रगति की समीक्षा करने और इसके बारे में एक कार्य योजना बनाने के लिए एक बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान, शहर में भूजल की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत की गई और शहर में व्यवहार्य स्थलों पर भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए गुट योजना पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि चंडीगढ़ में सभी सरकारी भवनों, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को नवंबर 2025 तक वर्षा जल संचयन संरचनाओं से संतृप्त किया जाना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि स्वायत्त निकायों, जैसे पीयू और पीजीआई, और हरियाणा, पंजाब और केंद्र की सरकारों को अपने परिसर में वर्षा जल संचयन प्रणाली बनाने के लिए सलाह जारी की जाए। सभी मौजूदा वर्षा जल संचयन प्रणालियों को जियो-टैग किया जाएगा।

मौजूदा वर्षा जल संचयन प्रणालियों (सरकारी और निजी) के लिए एक सफाई अभियान 1 से 7 मई, 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इसके लिए, पूरे अभियान में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। सीएसआर पहल के तहत सामुदायिक केंद्रों और स्कूलों में वर्षा जल संचयन प्रणाली बनाने की गुंजाइश पर भी चर्चा की गई। यह बैठक यूटी चंडीगढ़ में भविष्य की जल प्रबंधन नीतियों और संरक्षण रणनीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में काम करेगी। मंदीप सिंह बराड़ ने सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और वांछित ऑनलाइन सरकारी पोर्टलों पर अपलोड करने का निर्देश दिया।

बैठक में प्रेरणा पुरी, आईएएस, सचिव इंजीनियरिंग, अमित कुमार, आईएएस, आयुक्त नगर निगम चंडीगढ़, सौरभ कुमार, आईएफएस, मुख्य वन संरक्षक, निशांत कुमार यादव, आईएएस, उपायुक्त चंडीगढ़, ईशा कंबोज, एचसीएस, संयुक्त सचिव, स्थानीय सरकार, संजय अरोड़ा, मुख्य अभियंता, और नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद थे

कृत्रिम व आधुनिक अंगों से दिव्यांगों बनेंगे आत्मनिर्भर: उपायुक्त गुप्ता

उपायुक्त ने रोटरी क्लब द्वारा आयोजित शिविर में मुख्यअतिथि के रूप में करी शिरकत

संवाददाता
पंचकूला

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बुधवार को सैक्टर-12 ए रोटरी क्लब द्वारा आयोजित शिविर में मुख्यअतिथि के रूप में शिरकत की। उपायुक्त ने शिविर में दिव्यांगों को आधुनिक कृत्रिम अंग वितरित किए। उन्होने कहा कि कृत्रिम अंगों से उनका जीवन सुलभ हो जाएगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उपायुक्त ने शिविर में दिव्यांगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना व उन्हें कृत्रिम अंग के साथ बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होने सबसे पहले रोटरी क्लब को बधाई दी कि वे काफी वर्षों से दिवयांग व जरूरतमंदों की मदद करके पुण्य का कार्य कर रहे हैं। उन्होने कहा कि अपने परिवार के लिए तो हर कोई जी रहा है, ज्यादा महत्वपूर्ण है गरीब व दिव्यांगों की मदद कर उनकी हौसलाफजाई कर उनकी दुआएं लेना ऐसा करने से आत्मिक संतुष्टि व शांति मिलती है। उन्होने रोटरी क्लब व भारत विकास परिषद से महिला सशक्तिकरण पर भी कार्य करने पर बल दिया। उन्होने कहा कि लडका लडकी एक समान होते हैं। यह भेदभाव समाज से खत्म होना चाहिए। यदि बेटी पढ जाती है तो वह बडे से बडे क्षेत्र में कमाल दिखा सकती है। उन्होने कहा कि आज बेटियां खेलों में अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर मैडल जीतकर देश व हरियाणा प्रदेश का नाम चमका रही हैं। उन्होने कहा कि भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू महिला है। इसके अलावा जिला प्रशासन में महिलाओं का बोलबाला है। पंचकूला की उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त, सीएमओ भी महिलाएं हैं। उपायुक्त ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के रोहडू से आए दोनों पैरों से दिव्यांग मोहनलाल से बातचीत की व उनका आशीर्वाद लिया। रोटरी क्लब पंचकूला के प्रधान अश्वनी मित्तल ने बताया कि रोटरी क्लब पिछले काफी वर्षों से गरीब, जरूरतमंद व दिव्यांगों की मदद करके सेवा कर रहा है। उन्होने बताया कि आज हमने 50 दिव्यांगों को आधुनिक कृत्रिम अंग प्रदान किए हैं जिससे वो किसी पर निर्भर न रहकर स्वयं समाज में कार्य कर सम्मान से अपना जीवनयापन का सकते हैं। उन्होने बताया कि हमने अपने इस कार्यालय में कई व्यवसायिक प्रशिक्षण सिलाई, कढाई, ब्यूटी कोर्स, कम्प्यूटर शिक्षा जैसे विभिन्न कोर्स गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को करवा रहे है। उन्होने बताया कि रोटरी क्लब गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की पढाई का भी खर्च उठाने, उनकी किताबें, यूनिफार्म व कोचिग करने में भी मदद कर रहा है। उन्होने बताया कि रोटरी क्लब में पंचकूला को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

एसडीएम ने बरवाला व रायपुररानी अनाज मंडी का किया दौरा

संवाददाता
पंचकूला

एसडीएम चंद्रकांत कटारिया ने आज बरवाला व रायपुररानी अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने मंडी में पेयजल, साफ सफाई व टायलेट को चैक किया। उन्होने मंडी अधिकारियों को किसानों की फसलों का समय पर उठान व भुगतान करने के निर्देश दिए। इसमें कोताही की गुजाईश नही है। उन्होंने मंडी में मौके पर आडतियों से व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत की व सरसों व गेहूं की आडतियों द्वारा की गई तैयारियों के बारे में जानकारी ली। कटारिया ने मोईस्चर मीटर द्वारा गेहूं डालकर उसकी जांच की। उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को मंडी में किसानों व अन्य लोगों को दी जा रही सुविधा और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी गेहूं व सरसों की खरीद को लेकर गंभीर है। उनके निर्देश है कि किसानों को मंडियों में बेहतर सुविधाएं मिले व समय पर उनकी फसलों का उठान के साथ साथ भुगतान भी समय पर होना चाहिए। हरियाणाा राज्य विपणन बोर्ड बरवाला के सचिव सुरेंद्र ने बताया कि अभी गेहूं मंडियों में आनी शुरू हो गई है। उन्होंने एसडीएम को किसानों को किसी किस्म की परेशानी नही आएगी आश्वासन दिया। इस अवसर पर हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के सचिव सुरेंद्र ढांडा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

बरवाला व रापुररानी की मंडियों में अब तब 168 मीट्रिक टन सरसों की हुई खरीद

पंचकूला। जिला में रबी सीजन 2025-26 के दौरान सरसों की खरीद तथा उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में अब तक 168 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई है और 139 मीट्रिक टन सरसों का अब तक उठान किया जा चुका है। इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूलाए बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में गेहूं व सरसों की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि 168 मीट्रिक टन सरसों में से 89 मीट्रिक टन सरसों की खरीद रायपुरानी अनाज मंडी से और 79 मीट्रिक टन बरवाला अनाज मंडी से की गई। इसी प्रकार हैफेड द्वारा 139 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया गया जिसमें से 85 मीट्रिक टन रायपुररानी अनाज मंडी से तथा 54 मीट्रिक टन बरवाला अनांज मंडी से शामिल है।

कालका रेलवे स्टेशन पर एटीएम मशीन नहीं होने से यात्री हो रहे परेशान

कालका। कालका रेलवे स्टेशन पर या उसके पासपास एटीएम नहीं होने से यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एटीएम की सुविधा ना मिलने से देश विदेश से आने वाले सैलानियों के साथ अन्य लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कालका-शिमला रेलमार्ग को विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है, जोकि इस क्षेत्र की एक अपनी पहचान है। स्थानीय सामाजिक संगठन मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन (रजि.) के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन राय ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर अगर किसी सैलानी को कैश की जरूरत पड़ती है तो उसे स्टेशन के बाहर जाकर एटीएम की तलाश करनी पड़ती है, ट्रेन निकलने का भी डर बना रहता है। संगठन की ओर से रेलवे प्रशासन के उच्चाधिकारियों से अनुरोध है की यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही एटीएम की सुविधा प्रदान की जाए।

उपायुक्त द्वारा आरएएमपी के अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर का औपचारिक उद्घाटन

संवाददाता
चंडीगढ़

एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के भारत सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में, एमएसएमई मंत्रालय (एमओएमएसएमई) ने विश्व बैंक द्वारा समर्थित पांच वर्षीय प्रोग्राम-पी फॉर आर पहल -रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफार्मेंस (आरएएमपी) योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई की बाजारों और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संस्थागत और शासन संरचनाओं को मजबूत करना और एमएसएमई की स्थिरता को बढ़ावा देते हुए विलंबित भुगतान जैसे प्रमुख मुद्दों का समाधान करना है। चंडीगढ़ प्रशासन, आरएएमपी कार्यक्रम में सक्रिय भागीदार रहा है। मुख्य अतिथि निशांत कुमार यादव, सचिव उद्योग, चंडीगढ़ प्रशासन ने अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर का औपचारिक उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरूआत यूटी चंडीगढ़ के उद्योग निदेशक पवित्र सिंह द्वारा गर्मजोशी से स्वागत के साथ हुई निशांत कुमार यादव ने चंडीगढ़ में एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने में विभाग के प्रयासों की सराहना की, तथा आरएएमपी कार्यक्रम के तहत की गई महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार किया। उन्होंने निरंतर तकनीकी उन्नयन और संसाधनों की सुविधा के महत्व पर जोर दिया, ताकि एमएसएमई तेजी से विकसित हो रहे आर्थिक परिदृश्य में फल-फूल सकें। कार्यक्रम का समापन यूटी चंडीगढ़ के उद्योग निदेशक श्री पवित्र सिंह, पीसीएस द्वारा कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में शामिल सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मेसर्स ईवाईएलएलपी - आरएएमपीएसपीआईयू, चंडीगढ़ के समर्थन से तैयार यूटी की रणनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) 22 फरवरी, 2024 को भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी, और बाद में प्रस्तावित हस्तक्षेपों के लिए 43.07 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ एमओएमएसएमई द्वारा अनुमोदित की गई थी।

संक्षिप्त-समाचार

विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर कार्यशाला आयोजित

चंडीगढ़। बुधवार को सरकारी बौद्धिक विकलांग पुनर्वास संस्थान सेक्टर 31-सी चंडीगढ़ ने विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (ASD) से पीड़ित व्यक्तियों के उपचारात्मक हस्तक्षेप और व्यवहार प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का आयोजन GRIID कॉलेज के विशेष शिक्षकों, क्लिनिक कर्मचारियों और कॉलेज के छात्रों के लिए किया गया। कार्यशाला की वक्ता एक्शन फॉर ऑटिज्म (AFA) नई दिल्ली की अमृता बुजर बरुआ थीं। उन्होंने ASD से पीड़ित व्यक्तियों के प्रबंधन और प्रशिक्षण पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। कार्यशाला का उद्घाटन GRIID के संयुक्त निदेशक प्रोफेसर अजीत सिदाना ने किया। उनके साथ GRIID स्कूल की प्रभारी वंदना सिंह, GRIID की क्लिनिक प्रभारी डॉ. रीना जैन, GRIID के कोर्स समन्वयक डॉ. करुप्पासामी भी थे।

अस्पतालों में बदला ओपीडी का समय

चंडीगढ़। सरकारी मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल, सेक्टर-16, चंडीगढ़ और इसके संबद्ध स्वास्थ्य एवं औषधि केंद्र/डिस्पेंसरियां, सिविल अस्पताल मनीमाजरा, सिविल अस्पताल सेक्टर-22, चंडीगढ़ और सिविल अस्पताल, सेक्टर-45, चंडीगढ़ की ओपीडी का समय 16 अप्रैल, 2025 से 15 अक्टूबर, 2025 तक सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक रहेगा। ईएसआई डिस्पेंसरी-29 और ईएसआई-23, यू.टी., सेक्रेटरी और हाईकोर्ट डिस्पेंसरी का समय पहले की तरह ही रहेगा।

सिटको ने अपने होटलों में नवरात्रि थाली के बेहतरीन विकल्प पेश किए

चंडीगढ़। सिटको अपने प्रतिष्ठित होटलों में थाली के बेहतरीन विकल्प पेश करते हुए बेहद खुश है, जिसमें होटल माउंटव्यू, होटल शेफ लेकव्यू, होटल पार्कव्यू और होटल शिवालिकव्यू शामिल हैं। खास तौर पर तैयार की गई ये थालियाँ पारंपरिक स्वाद और त्यौहारी व्यंजनों का मिश्रण पेश करती हैं, जो खाने का एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती हैं। सिटको के शेफ ने अपने ग्राहकों के अलग-अलग स्वाद को ध्यान में रखते हुए इन थालियों को बहुत ही सावधानी से तैयार किया है। होटल माउंटव्यू ने अपनी खास थाली रु 550 में पेश की है, जिसमें स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट का एक बेहतरीन चयन है। होटल शेफ लेकव्यू, होटल पार्कव्यू और होटल शिवालिकव्यू अपनी नवरात्रि थाली क्रमशः रु 300, रु 300 और रु 450 में पेश करते हैं, जिनमें से प्रत्येक में पारंपरिक और त्यौहारी व्यंजनों का अनूठा मिश्रण है। सिटको के प्रबंध निदेशक श्री हरि कल्लिक्कट, आईएएस ने कहा, हम अपने प्रमुख होटलों में अपनी थाली की पेशकश शुरू करने से रोमांचित हैं। ये थालियाँ भारत की समृद्ध पाक परंपराओं का जश्न मनाती हैं, खासकर त्योहारों के मौसम में। हमारे शेफ ने हमारे मेहमानों के विविध स्वादों को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यंजन को सावधानीपूर्वक तैयार किया है। हम भोजन प्रेमियों को इन पौष्टिक और लजीज भोजन का स्वाद लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिटको सभी संरक्षकों को सीमित समय के लिए उपलब्ध इन दिव्य थालियों का आनंद लेने और अपने प्रतिष्ठित होटलों में प्रामाणिक और पौष्टिक व्यंजनों का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है।

मुख्य प्रधान सचिव ने परिवार सहित माता मनसा देवी व चंडी माता मंदिर में माथा टेक लिया आशीर्वाद

पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने अपनी धर्मपत्नी सोनिया त्रिखा के साथ श्री माता मनसा देवी में माथा टेका व पूजा अर्चना कर महामायी का आशीर्वाद लिया। इसके उपरांत मुख्य प्रधान सचिव ने माता मनसा देवी स्थित गौशाला में गौ माताओं को चारा खिलाया। इसके उपरांत राजेश खुल्लर ने चंडी माता मंदिर में माता के दर्शन किए व पूजा अर्चना की। इसके उपरांत उन्होंने हवन किया व हवन में आहुति डाली। उन्होंने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रों की बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उपायुक्त मोनिका गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त व सीईओ माता मनसा देवी निशा यादव, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, माता मनसा देवी की सचिव शारदा प्रजापति सहित श्रद्धालु उपस्थित थे।

चैत्र नवरात्र के पांचवे दिन 27 लाख 35 हजार 770 रुपए आया चढावा

पंचकूला। चैत्र नवरात्र मेले के तीसरे दिन आज श्री माता मनसा देवी, श्री काली माता मंदिर कालका मंदिर में श्रद्धालुओं ने पांचवे दिन 27 लाख 35 हजार 770 रुपए की राशि दान स्वरूप अर्पित की। माता मनसा देवी मंदिर में 40 हजार श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। श्री माता मनसा देवी मंदिर में 21 लाख 87 हजार रुपये, श्री काली माता मंदिर कालका में 5 लाख 48 हजार 770 रुपये दान स्वरूप अर्पित किए गए। इसके अलावा श्री माता मनसा देवी मंदिर में चांदी के 5 नग दान स्वरूप अर्पित किए गये।

नाटक में कनाडा में ज़िंदगी के कई गूढ़ कड़-वे सच किए गए उजागर

चंडीगढ़। नीतू शर्मा ने अपना लिखा और निर्देशित नाटक कनाडा दी पीआर थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ और सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, कनाडा द्वारा पंजाब कला भवन, चंडीगढ़ में खेला। कई सालों से कनाडा में रहने के कारण इस विषय की कुछ यादें और जड़ों ने उन्हें यह नाटक लिखने और खेलने के लिए प्रेरित किया, इसलिए वह खुद इस नाटक में मुख्य किरदार निभाते हुए नाटक मंचन के दौरान कई स्थानों पर संवाद और हाव-भाव में वहां की ज़िंदगी के कई गूढ़ कड़वे सच भी कह जाती हैं। नाटक 'कनाडा दी पीआर एक परिवार की कहानी है, जो कठिन संघर्ष और मेहनत करके वहां बस जाता है, पर नई पीढ़ी उन्हें दरकिनार करके अपनी अलग जिंदगी जीती है।

प्रॉपर्टी टैक्स वृद्धि का भाजपा ने किया कड़ा विरोध, तत्काल वापसी की मांग की

संवाददाता
चंडीगढ़

यूटी प्रशासन की ओर से शहर में प्रॉपर्टी टैक्स में की गई बढ़ोतरी को लेकर भाजपा की आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मेयर हरप्रीत कौर बबला ने की, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा, उपाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह बबला, और सभी भाजपा पार्षद उपस्थित रहे। बैठक के दौरान भाजपा पार्षदों ने सर्वसम्मति से इस अन्यायपूर्ण टैक्स वृद्धि का विरोध किया और इसे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने वाला फैसला करार दिया। पार्षदों ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय हाउस की मंजूरी के बिना लिया गया है, जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है। प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने कहा कि हम इस अव्यवहारिक और बिना किसी समुचित परामर्श के लागू किए गए कर वृद्धि का कड़ा विरोध करते हैं। यह फैसला आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डालने वाला है और भाजपा इसकी तत्काल वापसी की मांग करते हैं। मेयर हरप्रीत कौर बबला ने कहा कि भाजपा हमेशा चंडीगढ़ की जनता के साथ खड़ी रही है और हम इस फैसले के खिलाफ हरसंभव कदम उठाएंगे। नगर निगम और प्रशासन को जनता पर कर का बोझ डालने के बजाय खर्चों में कटौती और कार्यकुशलता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भाजपा पार्षद इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे और यदि आवश्यक हुआ तो जनता के साथ मिलकर व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। भाजपा चंडीगढ़ की जनता के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

एसीबी की टीम ने रिश्वत के आरोपी को किया गिरफ्तार

चंडीगढ़। एसीबी रोहतक द्वारा 1 अप्रैल को एएसआई आरोपी जितेन्द्र, सहायक क्लर्क को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी अनुसार शिकायतकर्ता ने एक शिकायत एसीबी रोहतक में दी कि पुलिस उपायुक्त कार्यालय झज्जर में सन्दीप उर्फ कालू व एएसआई जितेन्द्र द्वारा मिलीभगत करके शस्त्र लाईसैंस बनवाने में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस शिकायत पर थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक में मामला दर्ज किया गया तथा आरोपी संदीप उर्फ कालू उपरोक्त को दिनांक 17.4.2024 को ही गिरफ्तार किया गया था। आरोपी सन्दीप उर्फ कालू ने पूछताछ में बताया कि वह शस्त्र लाईसैंस बनवाने की एवज में रिश्वत के तौर पर पैसे लेता था जिसमें से कुछ पैसे वह आरोपी ए.एस.आई. जितेन्द्र कुमार को भी देता था।

निरंकारी कला एंव संगीत संस्थान में शिक्षा हासिल कर ट्रेनिंग पूरी करने वालों को बांटे सर्टिफिकेट

संवाददाता
चंडीगढ़

बुधवार को सन्त निरंकारी सत्संग भवन सैक्टर 30-ऐ चंडीगढ़ में सन्त निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संचालित निरंकारी इंस्टिट्यूट आफ म्युजिक एंड आर्ट में शिक्षा हासिल करने वाले शिक्षार्थियों को सर्टीफिकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर जोनल इंचार्ज ओ पी निरंकारी जी ने बताया कि यह संस्थान चण्डीगढ़ की प्राचीन कला केंद्र से सम्बन्धित है, यहां से किए गये तीन साल के कोर्स की मान्यता स्नातक डिग्री के समान है। इस संस्थान में कोई भी सज्जन संगीत सीखने या संगीत की डिग्री प्राप्त करने के भाव से केवल 300 रूपए प्रति माह की फीस देकर जितने समय के लिए वह चाहे संगीत सीख सकता है। इस केंद्र में संगीत के साथ साथ पेंटिंग और अन्य कला भी सिखाई जाएगी। निरंकारी जी ने आगे कहा कि आज इन्सान में इन्सान के प्रति प्यार की भावना खत्म होती जा रही है जिस कारण एक दूसरे का सत्कार भी नहीं हो रहा है। सत्कार भाव न होने से इन्सान का एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं रहा, तभी आज आपस में नफरत के भाव पैदा हो रहे हैं। आज नफरत को प्यार में बदलने की जरूरत है और इसका समाधान केवल समय के सत्गुरू की शरण में जाकर इस प्रभु परमात्मा की जानकारी करना जरूरी है।

आयोजन

कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के 250 से अधिक शोधकताओं और छात्रों ने भाग लिया

आईआईटी रोपड़ में राष्ट्रीय भौतिकी सम्मेलन हुआ संपन्न

संवाददाता
रोपड़/चंडीगढ़

आईआईटी रोपड़ ने राष्ट्रीय स्तर के भौतिकी सम्मेलन PHYCON-25 का सफलतापूर्वक समापन किया, जिसमें दो दिनों तक विचारोत्तेजक चचाओं और शोध प्रस्तुतियों के लिए अग्रणी वैज्ञानिक, शिक्षाविद और उद्योग के पेशेवर एक साथ आए। इस कार्यक्रम में भारत भर के विभिन्न संस्थानों के 250 से अधिक शोधकताओं और छात्रों ने भाग लिया। सम्मेलन की शुरूआत दीप प्रज्ज्वलन समारोह और विशिष्ट अतिथियों के सम्मान के साथ हुई।

PHYCON-25 के संयोजक और भौतिकी विभाग के प्रमुख डॉ. कैलाश सी. जेना ने आईआईटी रोपड़ में चल रही शोध गतिविधियों पर प्रकाश डाला। अपने उद्घाटन भाषण में, आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रो. राजीव आहूजा ने अंतःविषय सहयोग और मजबूत अकादमिक-उद्योग साझेदारी के महत्व पर जोर दिया, जिसमें सैद्धांतिक और अनुप्रयोग-उन्मुख अनुसंधान दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बौद्धिक चर्चा के केंद्र के रूप में कार्य करने के अलावा, PHYCON-25 का क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व भी है। प्रो. आहूजा ने वैज्ञानिक साक्षरता, शोध संस्कृति और नवाचार को मजबूत करने के लिए भारत के सक्रिय प्रयासों को रेखांकित किया। उत्तर-पश्चिमी भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की अपार संभावनाओं के साथ, आईआईटी रोपड़ इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पहले दिन RISE-TGC कोलकाता के निदेशक और IISER पुणे के एमेरिटस प्रोफेसर प्रो. सतीशचंद्र ओगले ने 'नई ऊर्जा और स्थिरता का विकसित परिदृश्यः बुद्धिमान सामग्री डिजाइन की शक्ति को उजागर करना' विषय पर एक पूर्ण वार्ता की, जिसमें बैटरी प्रौद्योगिकी, सौर सेल और उनके व्यावसायीकरण में प्रगति पर प्रकाश डाला गया।

उन्होंने उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच अच्छे संबंधों पर जोर दिया। दूसरा पूर्ण सत्र प्रो. आनंद झा, आईआईटी कानपुर ने 'आंशिक ऑप्टिकल सुसंगतताः क्वांटम स्टेट मापन और इमेजिंग में अनुप्रयोग' पर दिया। उनके भाषण ने क्वांटम इमेजिंग और ऑप्टिकल सुसंगतता में अत्याधुनिक तकनीकों पर प्रकाश डाला। दिन का समापन पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन, कविता पाठ और एक शानदार पंजाबी भांगड़ा की विशेषता वाली जीवंत सांस्कृतिक संध्या के साथ हुआ।

दूसरे दिन की शुरूआत टीआईएफआर हैदराबाद के निदेशक प्रोफेसर एम. कृष्णमूर्ति द्वारा 'अल्ट्राफास्ट लेजर का उपयोग करके तरल बूंदों को मिनी-एक्सीलरेटर में परिवर्तित करना' विषय पर एक विस्तृत चर्चा के साथ हुई, जिसके बाद मैकमास्टर विश्वविद्यालय, कनाडा के प्रोफेसर पीटर क्रूस ने 'जलीय वातावरण में अनुप्रयोगों के लिए रसायन प्रतिरोधक सेंसर' पर चर्चा की। उद्योग ट्रैक में नेक्सस एनालिटिकल्स और न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटीरियल्स की चचाएँ शामिल थीं, जिसमें अकादमिक शोध को औद्योगिक अनुप्रयोगों के साथ जोड़ने के महत्व पर बल दिया गया। अंतिम विस्तृत चर्चा आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर रघुनाथ साहू ने 'लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण' विषय पर की। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कण भौतिकी प्रयोगशाला, सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (एलएचसी) और बिग बैंग के दौरान प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों की नकल करने में इसकी भूमिका का एक आकर्षक अवलोकन प्रदान किया।

PHYCON-25 ने युवा शोधकताओं को अपने अत्याधुनिक शोध कार्यों और विचारोत्तेजक विचारों को वैज्ञानिक समुदाय के साथ साझा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया। इस प्रकार, इन दो दिनों के दौरान, विभिन्न संस्थानों के शोध विद्वानों ने प्रकाश-पदार्थ अंतःक्रिया, संघनित पदार्थ और परमाणु और उच्च-ऊर्जा भौतिकी पर मौखिक और पोस्टर प्रस्तुतियों के रूप में अपने कार्य प्रस्तुत किए। इन आकर्षक सत्रों ने भौतिकी के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का परीक्षण किया, जिज्ञासा और इंटरैक्टिव सीखने की भावना को बढ़ावा दिया। सम्मेलन का समापन एक पुरस्कार समारोह के साथ हुआ जिसमें उत्कृष्ट मौखिक और पोस्टर प्रस्तुतियों को मान्यता दी गई। PHYCON-25 की सह-संयोजक डॉ. रितु गुप्ता ने प्रतिभागियों, वक्ताओं, प्रायोजकों और आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन दिया। उन्होंने PHYCON-26 की भी घोषणा की, और भी अधिक नवाचारों और सहयोग का वादा किया।